

डालटनगंज (मेदिनीनगर)
शुक्रवार
04 जुलाई 2025

ईश्वर में हमारा विश्वास



सत्यमेव जयते



पेज 12

एक नजर

झारखंड रेल हादसा :

साहिबगंज में मालगाड़ी की 18 बोगी पटरी से उतरीं साहिबगंज। साहिबगंज में गुरुवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। इसमें पथरों से लोड एक मालगाड़ी बेपटरी हो गयी, जिससे कई बोगियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना में मालगाड़ी की करीब 18 बोगियां पटरी से उतरकर नीचे गिर गई हैं। मालदा डीआरएम घटनास्थल का मौका-मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साहिबगंज के बरहरवा हिल अपर साइड में गुरुवार की सुबह पथर चिप्स लोड्ड एक मालगाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे मालगाड़ी के डिब्बे घनी आबादी की तरफ आ गिरे लेकिन इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पहाड़ पर थी। जब मालगाड़ी पहाड़ से ढलान की तरफ आने लगी तो वह अनियंत्रित होकर सरकने लगी। इसके बाद देखते ही देखते मालगाड़ी की कई बोगियां आपस में टकरा गईं और पलटकर क्षतिग्रस्त हो गईं। मालगाड़ी में पत्थर चिप्स लोड था। दुर्घटना की आवाज सुनकर गांव वाले उभर की तरफ भागे तो देखा कि एक के बाद एक मालगाड़ी की बोगियां आपस में टकरा कर पलटी हुई हैं। वहां पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। कुछ ही देर बाद वहां पर सुरक्षा बल, प्रशासनिक और रेलवे के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठों को दी।

व्हाट्सएप
से सीधे जुड़ें

1994 से अनवरत हम आपके लिए समाचारों को प्रमुखता की नीति पर कार्य करते रहे हैं। इसे और सुगम बनाने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर

72094 53444 पर आप सीधे अपनी परखी हुई सच्ची खबर फोटो सहित संक्षेप में भेज सकते हैं। आपतिजनक बातें भेजने पर आइटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। यदि आपको अखबार की प्रति निजी मिल पा रही है या विज्ञापन देना चाहते हैं तो इस नंबर पर

72094 03444 संपर्क करें।

आज / कल

महाराष्ट्र में तीन महीने में 67 किसानों ने की आत्महत्या

हमारे पास खेत में काम करने के लिए हल है, पर जिम्मेदारों के पास हमारी समस्याओं का हल कोई नहीं है।

गढ़वा में नितिन गडकरी ने दी 2459.48 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

असली समृद्धि युवाओं को रोजगार से आएगी : गडकरी

● गढ़वा बाईपास का लोकार्पण, गुमला एनएच का शिलान्यास, तसर से सीएनजी तक विकास योजनाओं की झलक

राणा अरुण सिंह

गढ़वा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को गढ़वा पहुंचे और राज्य को 2459.48 करोड़ रुपये की दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने शंखा से खजुरी तक 23 किमी लंबे फोरलेन गढ़वा बाईपास (एनएच-39) को 1129.48 करोड़ की लागत से निर्मित कर लोकार्पित किया, जबकि गुमला जिले में छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक 32 किमी फोरलेन एनएच-43 के निर्माण कार्य का 1330 करोड़ की लागत से ऑनलाइन शिलान्यास किया।

हूर गांव के पास आयोजित समारोह में उन्होंने पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की मांग पर औरंगाबाद (बिहार) से डालटनगंज (झारखंड) तक 24 किमी सड़क निर्माण के लिए 670 करोड़ की मंजूरी दी। इसी साल से कार्य शुरू होने का भरोसा दिलाया। गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की मांग पर गढ़वा-अंबिकापुर फोरलेन परियोजना के लिए 4500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं, चतरा सांसद कालीचरण सिंह की मांग पर टोरी और



महुआमिलान में आरओबी निर्माण को भी मंजूरी मिली। गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में अब तक 40 हजार करोड़ की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 70 हजार करोड़ की योजनाएं पाइपलाइन में हैं और 75 हजार करोड़ की योजनाएं आगामी हैं। राज्य में कुल दो लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर काम होगा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें देश को समृद्ध बनाती हैं। झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है, लेकिन असली समृद्धि तब आएगी जब युवाओं को काम मिलेगा। उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ मॉडल का उल्लेख करते

हुए बताया कि वहां 1000 तालाब बनाकर किसानों की हालत सुधारी गई, झारखंड में भी ऐसी योजना लागू की जाएगी। तालाबों की खुदाई की मिट्टी से सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे पर्यावरण, कृषि और आधारभूत संरचना को एक साथ लाभ मिलेगा। गडकरी ने झारखंड की तसर साड़ियों और हस्तशिल्प की सराहना करते हुए कहा कि साहेबगंज और गोड्डा की महिलाएं जो साड़ियां बनाती हैं, उनकी देशभर में मांग है। मुंबई की एक मॉडल ने नागपुर में इन साड़ियों का प्रदर्शन किया और वर्तमान में 200 साड़ियों की वेंटिंग चल रही है। उन्होंने स्थानीय कलाकारों को



प्रशिक्षण व बाजार से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम में झारखंड के लिए 500 करोड़ रुपये के केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) की भी घोषणा की गई। गडकरी ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री से मिलकर इसका प्रस्ताव जल्द भेजें। उन्होंने वित्त मंत्री के उस कथन का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि "चुनाव तक राजनीति होनी चाहिए, उसके बाद विकास की राजनीति।"

मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की

और बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में गुरुजी के साथ होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, मेदिनीनगर विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व सांसद घुरन राम, राज्य दिशा समिति सदस्य दिवेश तिवारी, उपायुक्त दिनेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

3800 करोड़ की लगत से 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का हुआ शिलान्यास

गडकरी के एलिवेटेड कॉरिडोर से राजधानी रांची निहाल

● राजधानी को जाममुक्त करने का 4 दशक पुराना सपना हुआ पूरा

रांची। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गढ़वा के बाद रांची को भी गुरुवार को बड़ी सौगात दी। उन्होंने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले रांची पहुंचने पर नितिन गडकरी पर फूलों की बारिश की गई। इस स्वागत से केंद्रीय मंत्री अभिभूत दिखे। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 560 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नितिन गडकरी ने आज झारखंड में 6300 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

रांची में इलेक्ट्रिक बस और आउटर रिंगरोड की घोषणा की : नितिन गडकरी ने कहा, 'नागपुर के बाद रांची देश का दूसरा शहर होगा, जहां इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। ये बसें डीजल बसों की तुलना में 30% सस्ती होंगी।' उन्होंने रांची में आउटर रिंगरोड निर्माण को मंजूरी देने की घोषणा की और रातू रोड फ्लाईओवर के सौंदर्यीकरण के लिए आर्ट कॉलेज के छात्रों के सहयोग की बात कही। गडकरी ने बताया कि झारखंड में एक लाख करोड़ रुपये से सड़क निर्माण कार्य होगा, जिसमें कई परियोजनाएं शामिल हैं।

रांची-वाराणसी कॉरिडोर और अन्य परियोजनाएं : गडकरी ने बताया कि 413 किमी लंबा रांची-वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर साढ़े चार घंटे में तय होगा, जिसका 60% निर्माण पूरा हो चुका है। दिल्ली-कोलकाता 6-लेन कॉरिडोर में झारखंड का 128 किमी हिस्सा



रांची में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा

- आउटर रिंग रोड, रांची के डीपीआर को मंजूरी दी गई। ₹6000 करोड़ की लागत से बनेगा आउटर रिंग रोड।
- रातू रोड में नवनिर्मित एलिवेटेड कॉरिडोर के सभी पिलर पर सोहर्दाई पेंटिंग को तत्क्षण स्वीकृति।
- रांची-सिल्ली-मुुरी को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए गति शक्ति के तहत इसके निर्माण की संभावना तलाशेंगे।
- नागपुर की तर्ज पर रांची और जमशेदपुर में ई बस के परित्यालन का ट्रयाल करवाया जाएगा।
- ₹5000 + ₹500 करोड़ रुपए सीआरएफ (केंद्रीय सड़क फंड) के किए मंजूरी।
- एकतारी से मेहगामा खंड का 4-लेन निर्माण ₹1300 करोड़ की लागत।
- कोडमा-मेघातारी खंड का 4-लेन निर्माण को मंजूरी। लागत - ₹900 करोड़। इससे रांची और पटना के बीच बेहतर संपर्क प्रदान होगा।
- दोनो क्षेत्र में यात्रा समय। घंटे से घटकर 30 मिनट होगा। दुर्घटनाओं और यातायात संकुलन को कम करेंगे।
- पाकुड़ शहर में ₹450 करोड़ की लागत से 20 किमी लंबा बाइपास निर्माण।
- हंटरीगंज में बाईपास निर्माण ₹150 करोड़ की लागत से 7 किमी लंबा होगा यह बाईपास।

शामिल है, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है। रांची-सबलपुर और रक्सौल-हल्दिया (611 किमी) कॉरिडोर का निर्माण भी प्रस्तावित है। रांची-खूंटी 4-लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है,

जिसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की। **दिसंबर तक लॉजिस्टिक कॉस्ट घटकर नौ फीसदी हो जाएगा :** नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सात वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए

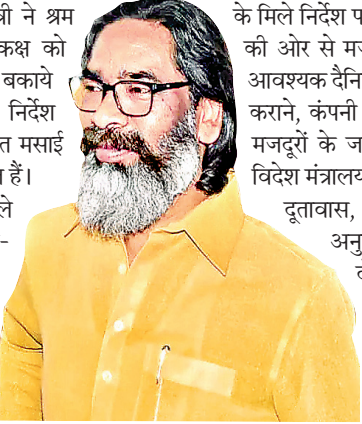
सालों पहले सीपी सिंह ने की थी फ्लाईओवर की मांग : नितिन गडकरी

एलिवेटेड कॉरिडोर को उद्घाटन करने के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि सालों पहले सीपी सिंह ने मुझे इस रास्ते पर लाकर कहा था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है। इसके बाद संजय सेठ लगातार मेरे पीछे लगे रहे। अधिकारियों ने मुझसे कहा कि यह सड़क शहर के बीचोबीच है, इसलिए इस काम को राज्य सरकार या नगर निगम को करना चाहिए। हालांकि, बाद में हमने संजय सेठ के दबाव में इस फ्लाई ओवर को बनाने का फैसला किया और अब यह बनकर तैयार है। इस फ्लाईओवर से रांची में प्रदूषण कम होगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।

हैं। लॉजिस्टिक कास्ट 16% से घटकर 10% हो गया है। दिसंबर से पहले लॉजिस्टिक कास्ट घटकर 9% हो जाएगा। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण देते हुए कहा कि कैनेडी ने कहा था **शेष पेज 11 पर...**

नवीन मेल संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद दुबई में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के 15 मजदूरों के वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से वतन वापसी में सहयोग की अपील की थी। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को मजदूरों के सुरक्षित वतन वापसी और बकायें पारिश्रमिक का भुगतान कराने का निर्देश दिया था। सभी 15 कामगार दुबई स्थित मसाई कान्ट्रैक्टिंग एलएलसी कंपनी में कार्यरत हैं। मजदूरों ने जानकारी दी कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। बार-बार अनुरोध के बावजूद कंपनी की ओर से वेतन भुगतान में टालमटोल की जा रही है। कंपनी की ओर से किसी प्रकार का वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जिन मकानों में वे रह रहे हैं, वहां मकान का किराया नहीं देने पर पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। वे वतन वापसी की व्यवस्था का आश्वासन कंपनी के प्रतिनिधि एनटी रेड्डी (महाप्रबंधक) ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को दिया है।



के मिले निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की ओर से मजदूरों को भोजन, पानी और आवश्यक दैनिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने, कंपनी से बकाया वेतन दिलाने एवं मजदूरों के जल्दपन वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय दूतावास, अबूधावी, दूतावास, दुबई से अनुरोध किया गया। इसके बाद दो जुलाई को कंपनी ने अप्रैल 2025 का वेतन कुल पांच लाख 55 हजार 242 रुपए भुगतान कर दिया। कंपनी ने शेष बकाया पारिश्रमिक का भुगतान करने और भारत वापसी की व्यवस्था का आश्वासन कंपनी के प्रतिनिधि एनटी रेड्डी (महाप्रबंधक) ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना गणराज्य की संसद को संबोधित किया, कहा हमारी देस्ती घाना के प्रसिद्ध अनानास से भी ज्यादा मीठी

अकरा (आईएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घाना गणराज्य की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि मैं घाना गणराज्य की संसद को संबोधित करके बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। घाना में होना सीमाध्य की बात है, यह एक ऐसी भूमि है, जो लोकतंत्र की भावना को प्रसारित करती है। दुनिया के सबसे बड़े



लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं 1.4 बिलियन भारतीयों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और सद्भावना

लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम घाना को देखते हैं तो हम एक ऐसे राष्ट्र को देखते हैं, जो साफस के साथ खड़ा है- एक ऐसा राष्ट्र, जो सम्मान और शांतिनता से हर चुनौती का सामना करता है। समावेशी प्रगति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने वास्तव में घाना को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए प्रेरणा का केंद्र बना दिया है। **शेष पेज 11 पर...**

इंडिया भ्रष्ट आइएस की बढ़ती संख्या से नौकरशाही की गिरती प्रतिष्ठा

25 साल का होने जा रहा झारखंड अपनी खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पर्यटन स्थलों से अधिक कथित भ्रष्ट बड़े अधिकारियों के कारण चर्चा में है। वरिष्ठ आईएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, छवि रंजन और पूजा सिंहल की गिरफ्तारी आरोपों ने न केवल सुर्खियां बटोरें बल्कि राज्य की छवि को भी धूमिल किया। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसेने वालों में 1999 बैच के आईएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को राज्य सरकार के एंटी कर्प्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का संचित रहते हुए शराब नीति में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं कीं, जिससे छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट को लाभ पहुंचा। इस घोटाले से राज्य को 38

करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ। एसीबी ने चौबे और संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया, जो इस मामले में एक और कड़ी हैं। यह आरोप नौकरशाही, राजनीति और निजी क्षेत्र की सांठगांठ से ही संभव हैं। हजारीबाग में उपायुक्त रहे श्री चौबे पर आरोप है कि हजारीबाग के खासमहाल की 2175 एकड़ जमीन का फजीी दस्तावेज के आधार पर 23 निजी लोगों को निर्बंधन कर दिया था। इससे पहले 2011 बैच के आईएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने रांची में सेना की जमीन से संबंधित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने रांची के उपायुक्त पद पर रहते हुए फजीी दस्तावेजों के आधार पर 4155 एकड़ सैन्य भूमि को बिक्री में सहायता की। रांची के बरियातू और चेशावर होम रोड जैसे क्षेत्रों में जमीन घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आई। ईडी की जांच में पता चला कि छवि रंजन ने जमीन माफिया व बिचौलियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की, जिससे सरकारी और आदिवासी जमीनों का दुरुपयोग हुआ। छवि रंजन अभी भी जेल में हैं और इन आरोपों ने श्रेष्ठ माने जाने



वाली नौकरशाही की गरिमा को प्रभावित किया है। 2000 बैच की आईएस अधिकारी पूजा सिंघल 21 साल की उम्र में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई थीं और सबसे कम उम्र की उपायुक्त रहते हुए उन्होंने 2008-10 के दौरान 10116 करोड़ रुपये की अनियमितता की। ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी में 19।31 करोड़ रुपये नकदी और 150 करोड़ की अधोपति संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए। इनके सीए सुमन

कुमार के घर से भी भारी मात्रा में नकदी मिली। पूजा सिंघल को दिसंबर, 2024 में जमानत मिली और उन्हें दोबारा पॉस्टिंग भी दी गई। राज्य में भ्रष्टाचार के कारणों की बात करें तो यहां के लोगों का जागरूक नहीं होना और अरबों की खनिज संपदा इसके मूल कारण हैं। विकास योजनाओं से लेकर खनन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। जमीन की हेराफेरी और शराब नीति में मनमानी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। घूस लेते रहे हाथ पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी तक साक्ष्य के अभाव में और प्रभावशाली लोगों के कारण छूट जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इन घोटालों ने झारखंड को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। ऐसे मामलों से राज्य की छवि को धक्का लगा है। एंटी कर्प्शन ब्यूरो लगातार रियल्ट आदि की मिलने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन यह प्रवृत्ति कम होने के बजाय बढ़ रही है। कई सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के पास आय से काफी अधिक धन है, जिसे लक्ष्य बनाकर कार्रवाई की जाए लोकपाल को सक्रिय किया जाए तो भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा

सकता है। टेंडर में मनमानी पर रोक के लिए प्रक्रिया को अधिकाधिक पारदर्शी बनाने से ऐसी शिकायतों में कमी आ सकती है। टर्न ओवर की बड़ी राशि जैसे मनमाने शर्तों के आधार पर पदाधिकारी पहले से ही यह तय कर लेते हैं कि अमुक एजेंसी को टेंडर देना है। ऐसे में सक्षम कंपनियों को तकनीकी खामी बताकर छोट दिया जाता है। इससे भ्रष्टाचार का पोषण होता है। शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार के इस खेल में चौबे अंतिम कड़ी नहीं हैं। आगे भी इस कड़ी में कई नाम जुड़ेंगे क्योंकि राज्य सरकार इस पर रोक के लिए तत्पर दिख रही है। 180 देशों की लिस्ट में भारत 96वें पायदान पर है जो पिछले 10 सालों में भारत की सबसे खराब रैंकिंग है। 2023 में भारत की रैंकिंग 93 थी यानी नए इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 3 पायदान की गिरावट आई है। वैसे सिर्फ नौकरशाही को भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे इस तंत्र के एक महत्वपूर्ण पुर्जे की तरह होते हैं जो फैसले लेते हुए दिखते हैं पर असल फैसले वो नहीं करते बल्कि पूरे तंत्र का नेतृत्व करने वाले नेता लेते हैं जो एक और इन्हें बढ़ावा देते हैं तो दूसरी ओर ईमानदार को किनारे कर देते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर जांबाज जवानों की ताकत

मिशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, हमारे देश के महापराक्रमी जांबाज जवानों की ताकत है और पहलगाम की वादियों में निर्दोष , मासूम प्रयटकों के खून बहाने वालों के बिरुद्ध प्रतिशोध की ज्वाला है। धर्म और जाति के नाम पर पाकिस्तान के क्रूर आतंकवादियों ने सिंदुरी खून से मेहंदी के रंग को फीका कर दिया , माता की गोद को सूना कर किया, बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया और पत्नि के मांग की सिंदूर मिटा दी। अब यही हिंदुस्तानी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तानी आतंकवाद का नामोनिशान मिटा देने का संकल्प ले चुका है। आज हमारे जवानों का शौर्य उनपर इस प्रकार कहर बन ढा रही है कि आज उनके लाशों को कन्या देने वाला कोई नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने अपना इतिहास रचने वाला अनोखा शौर्य दिखला कर दुश्मनों के सारे मनसुबे को ध्वस्त कर, देश का गौरव बढ़ाया है इसके लिए हम भारतवासी उन्हें बधाई देते हैं। आज पूरा विश्व इस ऑपरेशन

राष्ट्रीय नवीन मेल

जय हिंद

पूनम सिन्हा
भाव शिल्पा

सिंदूर की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक भी कंधे से कंधा मिला कर श्रेष्ठ और सटीक हथियार तैयार कर रहें हैं जिसका उपयोग हमारे वीर सैनिक बखूबी करते हुए पूरे संसार को अचँपित कर रहें हैं। नमन है हमारे माँ भारती के रक्षक, अपने कुल के गौरव , मनु वंशज, और मानवता के रखवाले वीर जवानों के **भारत माता की जय, जय हिन्द, जय हिन्द की सेना**

केंद्रीय टीम ने किया खाद्य आपूर्ति योजनाओं का निरीक्षण, पीवीटीजी लाभकों से संवाद भी हुआ

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा को लेकर 3 जुलाई को जिले में केंद्रीय निरीक्षण दल का भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस निरीक्षण अभियान की शुरुआत मेदिनीनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एफएसडी डिपो से हुई, जहां टीम ने गोदाम में रखे खाद्यान्न की भंडारण स्थिति की जांच की और मंडल प्रबंधक आशीष कुमार को आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात टीम चैनपुर प्रखंड पहुंची, जहां व्यापार मंडल स्थित धान अधिप्राप्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया। वहां 2024-25 खरीफ सत्र के अंतर्गत धान की खरीद, उठाव और किसानों को किए गए भुगतान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही टीम ने राज्य खाद्य निगम के चैनपुर स्थित गोदाम का



भी दौरा किया और खाद्यान्न रख-रखाव की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।
जन वितरण प्रणाली दुकानों का भी निरीक्षण : टीम ने चैनपुर के दो जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण कर कार्डधारियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने राशन उठाव, वितरण, फोटीफाइड चावल और 'वन नेशन, वन राशन कार्ड'

योजना की जानकारी लाभकों को दी। दुकान पर उपस्थित लाभकों से यह भी पूछा गया कि उन्हें समय पर राशन मिल रहा है या नहीं।
पीवीटीजी परिवारों से किया सीधा संवाद : निरीक्षण के दौरान टीम कटीन टोला (चैनपुर) के पीवीटीजी समुदाय से भी मिली और उनसे अगस्त 2025 तक के खाद्यान्न प्राप्ति

की जानकारी ली। कार्डधारियों ने बताया कि उन्हें प्रत्येक माह नियमित रूप से खाद्यान्न घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित बच्चों को खाद्य सामग्री भी वितरित की गई।
पीजी पोर्टल शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद : परिसदन भवन में पीजी पोर्टल के अंतर्गत प्राप्त

शिकायतों के समाधान की स्थिति को लेकर टीम ने शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद किया और समाधान से संतुष्टि की जानकारी ली।
उपायुक्त से की समीक्षा बैठक निरीक्षण उपरांत केंद्रीय दल ने उपायुक्त से भेंट कर अब तक किए गए निरीक्षण की विस्तृत जानकारी साझा की और विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय टीम में निदेशक गोकुल नागरकोटी और एफडी-3 सेक्शन के अधिकारी रामानंद मीणा शामिल रहे।
जिला स्तरीय उपस्थिति : जिला स्तर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कु, भारतीय खाद्य निगम मंडल प्रबंधक रंधीर कुमार, चैनपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ललन कुमार, पाटन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अक्षय कुमार, प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार तथा कंयूटर ऑपरेटर अंजय कुमार सहित अन्य कर्मी निरीक्षण में शामिल रहे।

मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न डीसी-एसपी ने सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की

● जुलूस खत्म होने तक भारी वाहनों को शहर से दूर रखें : एसपी

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में गुरुवार को स्थानीय टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी मोहर्रम पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि पलामू जिला त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए जाना जाता है, और इस परंपरा को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने समिति के सदस्यों से आपसी सहयोग और समन्वय के साथ इस बार भी मोहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का आह्वान किया।
बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन को ऑन कॉल एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने और सहायक नगर आयुक्त को सफाई के लिए डेडीकेटेड टीम तैनात करने का निर्देश दिया। साथ ही



टाउन थाना में फायर ब्रिगेड वाहन को रेडी टू यूज की स्थिति में रखने पर भी जोर दिया गया। त्योहार के दौरान साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, जुलूस मार्गों की सुरक्षा, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी, अफवाहों की रोकथाम, यातायात नियंत्रण और सोशल मीडिया की निगरानी जैसे विषयों पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि मोहर्रम जुलूस के दौरान शाम के समय भारी वाहनों को शहर में प्रवेश न दें। जुलूस समाप्त होने के बाद ही मार्ग पर इन्हें अनुमति दें। सीमा क्षेत्रों के थाना प्रभारी अपने निक्कटवर्ती दूसरे राज्य के थानों से समन्वय बनाए रखें। उन्होंने एनएचआई प्रतिनिधियों से समन्वय कर निर्माण कार्यों में लगे

वाहनों को व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने को कहा। एसपी ने यह भी कहा कि जुलूस अगर नदी या तालाब के समीप से गुजरता है तो पुलिसकर्मी सतर्क रहें और सुरक्षा सुनिश्चित करें। सभी पेट्रोलिंग वाहनों में फर्स्ट एड किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, इस पर सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखने की बात कही गई। बैठक में मोहर्रम इंतजामिया कमिटी, अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव और आवश्यक व्यवस्थाओं से डीसी-एसपी को अवगत कराया। बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी एसडीओ, डीएसपी, सीओ, थाना प्रभारी और संबंधित समिति के सदस्य उपस्थित थे।

मध्यस्थता को लेकर डालसा सक्रिय सचिव ने मीडिएटरों संग की समीक्षा बैठक

● न्यायाधीश दिवाकर पांडेय के मार्गदर्शन में 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे पर जोर



मेदिनीनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशानुसार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के तत्वावधान में 'मेडिएशन फॉर द नेशन - राष्ट्र के लिए मध्यस्थता' अभियान के तहत 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), पलामू के सचिव राकेश रंजन ने बुधवार को जिले में कार्यक्रम मध्यस्थों (मीडिएटर) के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति और आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में सचिव ने सभी मीडिएटरों से आग्रह किया कि अभियान की भावना को साकार करते हुए

ज्यादा से ज्यादा लंबित वादों का आपसी समन्वय से समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, ऋण वसूली, सुलहनीय आपराधिक और दीवानी वाद जैसे मामलों को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की विशेष पहल की जा रही है। सचिव राकेश रंजन ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य विवादों का तेज, सुलभ और आपसी सहमति से समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे पक्षकारों को न्यायालयीय प्रक्रिया में समय, खर्च और मानसिक तनाव से मुक्ति मिले। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता विवाद सुलझाने का एक मानवीय और

संवेदनशील तरीका है, जो समाज में समरसता और शांति स्थापित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय स्वयं इस अभियान की नियमित समीक्षा कर रहे हैं और न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को मध्यस्थता केंद्र में रेफर करें, ताकि वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली के तहत प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में उपस्थित सभी मीडिएटरों ने अभियान को सफल बनाने की प्रतिबद्धता जताई और जिले में लंबित मामलों के समाधान के लिए समर्पित प्रयास का आश्वासन दिया।

मुहर्रम को लेकर पुलिस की हाई अलर्ट बैठक अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। पलामू जिले में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पुलिस कप्तान रीष्मा रमेशन ने की। बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी, निरीक्षक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस कप्तान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुहर्रम पर्व के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा



और ड्रोन कैमरे से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार की अफवाह की स्थिति में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर साइबर सेल को अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी भड़काऊ पोस्ट

या अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई हो सके। खुफिया विभाग को सक्रिय किया गया है। पुलिस कप्तान ने आमजन से भी अपील की कि वे पर्व को सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या कंट्रोल रूम को दें।

दहेज उत्पीड़न का मामला, महिला के पिता ने पति और ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप
मेदिनीनगर। शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगना निवासी बैजनाथ पाठक ने अपनी पुत्री के ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री की शादी वर्ष 2009 में अलीगंज के लोहड़ी निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। आवेदन में बताया गया कि दामाद वर्तमान में रांची में रहता है और लड़की के दो बेटियाँ हैं। पुत्र न होने पर ससुराल वाले उसकी बेटी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री के साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकालने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में महिला ने पति, सास, ससुरा और पति की भतीजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पलामू में दो दिनों की हल्की बारिश से किसानों को राहत, शहरी क्षेत्र में जलजमाव से बढ़ी दिक्कतें

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। पलामू जिले में बीते चार दिनों की लगातार बारिश के बाद गुरुवार को हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। बारिश थमते ही खेतों में बिचड़ा डालने और जुताई का काम तेज हो गया है। वहीं, जिला मुख्यालय सहित शहरी इलाकों में जलजमाव की समस्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। खुली नालियों व सड़कों पर जमा पानी के कारण सड़कमक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।
गुरुवार को हल्की बारिश के बाद दिन में तेज धूप निकलने से तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो पिछले दो दिनों में लाम्बाग तीन डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में मई और जून में रिकॉर्ड से वर्षा हुई है। गुरुवार को 5.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि मंगलवार को 10.8 मिमी बारिश



हुई थी। शुक्रवार को भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
उधर, शहरी क्षेत्र के कचहरी परिसर में बने गड्ढों और जलजमाव से भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से एसडीएम कार्यालय के पास बने गड्ढे में पानी भरने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शोध गड्ढों की मरम्मत की मांग की है ताकि आवागमन सुचारु हो सके।

भोगनाडीह कांड के विरोध में झामुमो ने किया भाजपा का पुतला दहन

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। संथाल परगना के भोगनाडीह में 30 जून को हुए कथित अपमानजनक घटनाक्रम के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने शुक्रवार को पलामू जिले के छः मुहान चौक पर भाजपा का पुतला दहन किया। इस विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया।
इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। पुतला दहन के मौके पर जिलाध्यक्ष मिटाने की साजिश रच रही है और राज्य की शांति को भंग करने पर तुली हुई है। झामुमो इस तरह की साजिशों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जनता के साथ मिलकर संघर्ष करता रहेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय समिति सदस्य सन्नी सिद्दीकी, महिला नेत्री सुशीला मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष बालकिशुन उरांव, जिला सचिव रंजन चंद्रवंशी, रमेश सिंह,



सीधा अपमान है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी संस्कृति और इतिहास को मिटाने की साजिश रच रही है और राज्य की शांति को भंग करने पर तुली हुई है। झामुमो इस तरह की साजिशों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जनता के साथ मिलकर संघर्ष करता रहेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय समिति सदस्य सन्नी सिद्दीकी, महिला नेत्री सुशीला मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष बालकिशुन उरांव, जिला सचिव रंजन चंद्रवंशी, रमेश सिंह,

देवानंद भारद्वाज, राकेश सिन्हा, सुनील तिवारी, हाजी ललन, अविनाश देव, गोपाल सिन्हा, कांती चंद्रवंशी, फज़िल अहमद, मंजू कुमारी, शाहबाज आलम, दीपु चौरसिया, बबलू शहनवाज, रिशु अग्रवाल, बबलू चौधरी, अरविंद चौधरी, रंजन कुमार, कौशल किशोर, सैयद फैजल, रंजीत तिवारी, संजय तिवारी, कौशल सिंह, सौरभ पाठक, कौशिक राज, योगराज कुमार, अवधेश कुमार, अरुण, विकास, राजू समेत सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आस्था धार्मिक उल्लास के साथ निकली जैन समाज की मय्य कलश यात्रा

सिद्धचक्र विधान का शुभारंभ, तीन सौ से अधिक श्रद्धालु शामिल

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। गुरुवार को मेदिनीनगर में जैन समाज के श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा स्थानीय जैन मंदिर से प्रारंभ होकर छमुहान, ओवरब्रिज, रेड्मा होते हुए गणेश लाल सरावगी स्मृति परिसर, आबादगंज में संपन्न हुई। कलश यात्रा में महिलाओं ने एक जैसे पारंपरिक परिधान में अभिर्भ्रित जल से भरे कलश सिर पर लेकर भाग लिया। वहीं पुरुष केसरिया धोती-दुपट्टा पहनकर भक्ति में लीन रहे। रथ में भगवान की



प्रतिमा को विराजमान कर बैंड बाजा के साथ अनुष्ठान स्थल तक लाया गया। यात्रा में अष्टकुमारियों और लोकोत्तिक देव स्वरूप बच्चों ने विशेष

आकर्षण पैदा किया।
समारोह में बल ब्रह्मचारी अन्नू भैया के सान्निध्य में अगले आठ दिनों तक विधान संपन्न होगा। प्रतिदिन

प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था
कलश यात्रा के मार्ग में पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यातायात नियंत्रण के लिए कुछ जवान यात्रा के साथ-साथ मौजूद रहे ताकि आमजन को असुविधा न हो और जुलूस सुचारु रूप से आगे बढ़ सके। यातायात प्रभारी समाल अहमद ने जानकारी दी कि कलश यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। उन्होंने बताया कि अबादगंज में यात्रा का समापन सफलता पूर्वक कर लिया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली, और पूरा आयोजन प्रशासन एवं जैन समाज के सहयोग से सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

संध्या सात बजे भक्तामर स्तोर के 48 दीपों के साथ आरती और प्रश्न मंच कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में जैन समाज के वरिष्ठ

नागरिकों एवं अध्यक्ष सरस जैन की उपस्थिति रही। आयोजन में भक्ति, अनुशासन और भव्यता का अद्भुत समन्वय देखने को मिला।

बिजली सरचार्ज प्रस्ताव पर चेंबर का विरोध आंदोलन की चेतावनी

मेदिनीनगर। झारखंड सरकार द्वारा निगम क्षेत्र में बिजली पर 5% सरचार्ज लगाए जाने के प्रस्ताव पर पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कड़ा विरोध जताया है। चेंबर अध्यक्ष आनंद शंकर ने इसे जनता के साथ अन्याय करार देते हुए कहा कि सरकार नागरिकों को 'दुधारू गाय' समझ रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही व्यापारी वर्ग ऑनलाइन मार्केट और बड़े मॉल से परेशान हैं, ऊपर से गुणवत्ता विहीन बिजली मिलने के बावजूद सरकार अतिरिक्त चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है। यदि सरकार यह प्रस्ताव वापस नहीं लेती है, तो राज्यव्यापी आंदोलन तय है, जिसमें पलामू चेंबर भी भागीदार होगा। बैटक में रीजनल उपाध्यक्ष रिकू दुबे, अविनाश वर्मा, कृष्ण अग्रवाल, महामंत्री इंद्रजीत सिंह डिंपल, अरविंद गुप्ता, रादेव उपाध्यक्ष, राकेश सोनी समेत अन्य सदस्यों ने भी विरोध जताया।

छः मुहान पर चला वाहन चेकिंग अभियान 22,320 का जर्माना वसूला

मेदिनीनगर। शहर के व्यस्ततम छः मुहान चौक पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से गुरुवार को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में कई वाहन चालक बिना हेलमेट, बिना इंडीविंग लाइसेंस तथा ट्रिपल लोड सवारी करते हुए आए गए। ऐसे कुल 11 दोपहिया वाहनों को जब्त कर शहर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी चालक को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। उक्त वाहन को भी जब्त कर उसका चालान जिला परिवहन कार्यालय, पलामू को भेजा गया। साथ ही एक कार पर ब्लैक शीशा लगे होने के कारण भी कार्रवाई की गई और उसका चालान काटा गया। तीन जुलाई 2025 को जिला परिवहन कार्यालय, पलामू की ओर से भेजे गए चालान फाइन की राशि में 10 दोपहिया मोटरसाइकिलों का जर्माना कुल 11,150 निर्धारित किया गया। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर 10,170 का चालान फाइन लगा। इसके अतिरिक्त कारली शोशे वाली कार पर 1,000 का चालान फाइन लगाया गया। कुल मिलाकर इस चेकिंग अभियान में 22,320 का चालान फाइन राशि की वसूली हुई। यातायात प्रभारी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित वाहन संचालन को प्राथमिकता दें।



जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पलामू व्यवहार न्यायालय, पलामू			
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय नालसा व झालसा के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, पलामू के तत्वाधान में दिनांक 01 जुलाई 2025 से लेकर 30 सितम्बर 2025 तक 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित विभागों के वादों का निपटारा आपसी सुलह-समझौता के आधार पर किया जायेगा:-			
1.	वैवाहिक विवाद से संबंधित वाद / मामले		
2.	घरेलू हिंसा से संबंधित मामले		
3.	मोटरयान दुर्घटना से संबंधित मामले जिसमें दुर्घटना प्रतिवेदन एवं राज्य परिवहन विभाग से संबंधित मामले शामिल हो		
4.	पराक्रम्यविलेख की धारा 138 के मामले		
5.	व्यवसायिक विवादों से संबंधित मामले		
6.	सेवा से संबंधित मामले		
7.	सुलहनीय आपराधिक मामले		
8.	उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामले		
9.	ऋण विवाद से संबंधित मामले		
10.	विभाजन विवाद से संबंधित मामले		
11.	बेदखली विवाद से संबंधित मामले		
12.	भूमि अधिग्रहण विवाद से संबंधित मामले		
13.	अन्य उपयुक्त सिविल वाद		
अतः आप सभी आम नागरिक से निवेदन है कि इस अभियान के तहत स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पलामू में उपस्थित होकर इस अभियान का लाभ उठावें।			
नोट: विशेष जानकारी के लिए संपर्क कर टोल फ्री नं० 15100 तथा मोबाईल नं० 8757269596			
श्रीमती शीणा रमेशन	श्रीमती समीरा एस	श्री दिवाकर पाण्डेय	
पुलिस अधीक्षक,	उपायुक्त सह उपाध्यक्ष,	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,	
—सह—	—सह—	—सह—	
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष	
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,	जिला विधिक सेवा प्राधिकार,	जिला विधिक सेवा प्राधिकार,	
पलामू	पलामू	पलामू	

न्यूज बॉक्स

भरनो ब्लॉक चौक पर टाईगर जयराम महतो का हुआ भव्य स्वागत

गुमला। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को लेकर चर्चित जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो एवं डुमरी विधायक जयराम महतो का आज गुमला जिला प्रवेश के दौरान भरनो ब्लॉक चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रखंड अध्यक्ष बप्पी उरांव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका स्वागत किया। महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार जयराम महतो के पैर धोए और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक महतो ने कहा की जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते। वर्तमान समय में जिस तरह से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास हो रहे हैं, वह चिंताजनक है। इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा।”

सिसई में डुमरी विधायक का किया गया स्वागत

सिसई (गुमला)। झारखंड में टाईगर के नाम से प्रसिद्ध जेएलकेएम नेता सह डुमरी विधायक जयराम महतो का गुरुवार को गुमला में निर्धारित एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुमला जाने के दौरान सिसई प्रखण्ड मुख्यालय में झारखंड आंदोलकारी, जेएलकेएम कार्यकर्ता एवं सिसई के जनता काफी समय से इंतजार कर रहे थे। शाम पांच बजे जब जयराम महतो का काफिला सिसई पहुंचा तो झारखंड आंदोलनकारियों के विशेष अनुरोध पर कुछ समय के लिए अपने काफिले के साथ रुके। जहां झारखंड आंदोलनकारी मनोज वर्मा, जीतवाहन साहु, जुबेर अंसारी एवं जेएलकेएम के गुमला जिला महासचिव विनय कुमार साहु, सिसई प्रखंड महासचिव लालनंद किशोर नाथ शर्हदेव ने फूलमाला पहनाकर एवं बुके देकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं विधायक जयराम महतो ने प्रखण्ड मुख्यालय में स्थापित अम्बेडकर वाटिका में जाकर बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात प्रखण्ड परिसर में ही बने ललित उरांव के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जेएलकेएम कार्यकर्ताओं द्वारा जयराम महतो जिंदबाद,झारखंड का टाईगर जयराम महतो जिंदबाद जैसे नारा लगाया जा रहा था।

शिक्षकों की गुरु गोष्ठी आयोजित भरनो (गुमला)। भरनो प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कार्तिक उरांव पुस्तकालय सभागार में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय गुरुगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इ स बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रीति कुनूर ने की, जिसमें क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक आवश्यक प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित हुए। गोष्ठी में मध्याह्न भोजन योजना के मासिक प्रतिवेदन, 2024–25 की किट उपयोगिता प्रमाण पत्र, छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड व बैंक खाता, यूडीआइएस अपडेट, पुस्तक वितरण, एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) का पुनर्गठन, पारा शिक्षकों की सर्विस बुक अपडेट, नवोदय विद्यालय नामांकन, इंस्पายर्ड अवार्ड, आपाट आइडी, उपस्थिति रिपोर्ट समेत विद्यालय से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शिक्षकों से सभी जरूरी प्रतिवेदन एकत्र किए गए एवं कार्यों को समयबद्ध रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कार्तिक उरांव पुस्तकालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने तथा पुस्तकालय में अधिक से अधिक नामांकन कराने पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर बीपीओ सूरज लकड़ा, बीआरपी समीम एजाज, विजय कुमार, नूर एहसान, अशोक तिवारी सहित सभी सीआरपी और प्रधानाध्यापक उपस्थित थे।

कल होगा एक दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन

गुमला। “वर्ल्ड बैडमिंटन डे” के अवसर पर 5 जुलाई 2025 को गुमला जिले में एक दिवसीय भव्य बैडमिंटन प्रतियोगिता स्मैशथॉन-2025 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा इनडोर स्टेडियम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने गुरुवार को इनडोर स्टेडियम परिसर में बैडमिंटन कोर्ट के लिए लगाए गए नए हाई-ग्रेड मैट का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उन्हें नशा मुक्त जीवन अपनाने और खेल को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। उपायुक्त महोदया ने बच्चों एवं युवाओं को खेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया और खुद भी बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

चैनपुर और घाघरा में आमजनों की समस्याओं हुआ निष्पादन

गुमला। आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त गुमला के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में नियमित रूप से जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को चैनपुर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में शिविर का आयोजन हुआ, जिसकी संयुक्त अध्यक्षता घाघरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी ने की। जनसुनवाई शिविर के दौरान कुल 104 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 99 मामलों का निष्पादन मौके पर ही संबंधित विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा कर दिया गया, जिससे लोगों को त्वरित राहत मिली।

एसडीपीओ व थाना प्रभारी को गुमला चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया सम्मानित
गुमला। गुमला चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा गुमला पुलिस प्रशासन की सराहनीय सेवाओं के लिए एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव एवं थाना प्रभारी महेंद्र करमाली को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान गुरुवार, 3 जुलाई को गुमला पुलिस में बलब भवन में आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान प्रदान किया गया।

जल जीवन मिशन की प्रगति पर उपायुक्त ने जताई सख्ती

कार्य में तेजी व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश

नवीन मेल संवाददाता

गुमला। जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु बुधवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त कक्ष में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में एक विशेष समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गुमला अंतर्गत कार्यान्वित बहु-ग्रामीण एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपस्थित संवेदकों से योजनाओं की प्रगति, कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों और संभावित पूर्णता की समय-सीमा के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

खुशरेन बिल्डर्स, वैष्णवी इंटरप्राइजेज एवं अभिषेक सोलर के प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने संबंधित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की प्रस्तुति दी गई। उपायुक्त ने सभी संवेदकों को निर्दिशित किया कि कार्यों में तेजी लाएं, निर्धारित समयसीमा के भीतर योजनाओं को



डीसी की अध्यक्षता में पीएम जनमन योजना की हुई समीक्षा बैठक आयोजित

गुमला। गुरुवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जनजातीय जनमन योजना (पीएम जनमन योजना) के तहत विभिन्न विभागों को समन्वयात्मक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित विभागों के सभी अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त ने योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूहों तक सभी बुनियादी सुविधाएं सुचारू रूप से पहुंचाई जा सकें। उपायुक्त ने योजना के अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय किस्त से संबंधित अद्यतन जानकारी ली तथा लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि जिले के सभी पीबीटीजी ग्रामों में जल आपूर्ति योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

हर हाल में पूर्ण करें तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न

मनरेगा और आवास योजनाओं का डीडीसी ने किया स्थलीय निरीक्षण



नवीन मेल संवाददाता

गुमला। उपायुक्त गुमला के निर्देशानुसार 2 जुलाई 2025 को उप विकास आयुक्त दिलेवर महतो ने भरनो प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रही योजनाओं का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने योजनाओं की भौतिक प्रगति, कार्य की गुणवत्ता एवं श्रमिकों की उपस्थिति की गहन जांच की। कार्य स्थलों पर उपस्थित लाभुकों एवं श्रमिकों से उन्होंने सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं

और सुझावों को सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को उनके त्वरित समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी कार्य स्थलों पर सोशल ऑडिट बोर्ड, मस्टररोल, एवं सूचना पट्ट अद्यतन स्थिति में लगे हों। इसके साथ ही, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और श्रमिक हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की कइ। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, कनीय अभियंता, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

गांव में अभी तक नहीं पहुंची है कच्ची या पक्की कोई भी सड़क

नवीन मेल संवाददाता

सिसई (गुमला)। सिसई प्रखंड अंतर्गत मुर्गू के एकमात्र पुर्वज के वंशजों का दो दर्जन अनुसूचित जनजाति परिवार के करीब 130 सदस्यों का बसा गांव मेडयाटोली। प्रखंड स्थित दो दशक पुर्व घोर नक्सली दंश झेल चुके इस गांव में वर्तमान में सरकारी योजना के नाम पर पेयजलापूर्ति योजना के तहत बना एक जलमीनार है जो ढाई साल से खराब पड़ा हुआ है, विभिन्न घरों में शौचालय बना है। इक्के-दुक्के परिवारों को ही पक्का मकान मिला है। आजादी के 78 साल बाद भी इस गांव में पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। गांव के पाहान वायोवूड बिरिया उरांव, बंधुनु उरांव, जतन उरांव, दिलीप उरांव, शिवनाथ उरांव, बंधना उरांव, सुकरमनी उरांव, मंगलमुनी उरांव, बेसांगी उरांव,सुल्ला उरांव, जौनी देवी, सहित दर्जनों लोग बताते हैं कि दक्षिणी कोयल नदी तट के किनारे और मुर्गू-सुपाली गांव के पास बसा मेडयाटोली गांव है, लेकिन आज तक इस गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मुर्गू तक जाने वाली सड़क से पश्चिम



की ओर करीब एक किलोमीटर पर बसे गांव में पक्की तो छोड़िए कच्ची सड़क भी नहीं है, लोग आने जाने के लिए खाली पड़े खेत के पगडंडी और ईस्टर से बने रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी और जाड़े में तो किसी तरह गुजारा हो जाता है। मुसीबत तो बरसात में होती है जब गांव की किसी गर्भवती महिला, बीमार पड़े महिला-पुरुष, वृद्ध व बच्चे, चलने फिरने में असमर्थ लोगों को इलाज के लिए ले जाना हो या रोजमर्रा की जरूरत के लिए आना-जाना पड़ता है। सड़क नहीं होने को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों, नेताओं व अफसरों से बोलने के बाद भी इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।

एसडीओ सदर राजीव नीरज ने किया सिसई प्रखंड अंतर्गत पंडरिया पंचायत का निरीक्षण

नवीन मेल संवाददाता

गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थानों की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु एसडीओ सदर राजीव नीरज द्वारा सिसई प्रखंड अंतर्गत पंडरिया पंचायत का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना तथा पंचायत भवन का स्थलीय जायजा लिया। विद्यालय निरीक्षण के क्रम में उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की संख्या और मध्याह्न भोजन योजना की प्रगति की समीक्षा की। पीडीएस दुकान में खाद्यान्न वितरण की नियमितता, स्टॉक रजिस्टर की

एसडीओ ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण
गुमला। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर एसडीओ सदर राजीव नीरज ने आज सदर अस्पताल, गुमला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं, मरीजों को दी जा रही सेवाओं, दवा वितरण, स्वच्छता व्यवस्था, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति तथा अपातकालीन कक्ष की कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन किया। एसडीओ सदर ने ओपीडी, वार्ड, प्रसव कक्ष एवं जांच कक्ष का भ्रमण करते हुए मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद किया और अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता पर फीडबैक प्राप्त किया।

अद्यतन स्थिति तथा लाभुकों की संतुष्टि की जानकारी प्राप्त की। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सकों की उपस्थिति और आवश्यक दवाओं

की उपलब्धता का आकलन किया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत चल रही पौधरोपण, गड्ढा खुदाई एवं पौध वितरण की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।

पानी के लिए परेशान है चार पंचायतों के लोग

सिसई (गुमला)। ग्रामीण पेयजल पूर्ति योजना के तहत सिसई थाना के सामने बने विशालकाय पानी टंकी से एक माह से अधिक समय से चार पंचायत के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है जिसके कारण उन्हें घरेलू कार्यों को करने में कठिनाई हो रही है। पानी सप्लाई के बंद होने के बारे में पूछे जाने पर पीएचडी विभाग के जेईई रतन खलखो ने जानकारी देते हुए बताया कि डब्ल्यू टी पी का इंटेक वेल् का स्टार्टर और पैनल बोर्ड खराब हो गया है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बंद हो गई है। वहीं उन्होंने विशेष रूप से जानकारी देते हुए बताया की जलापूर्ति योजना से सिसई पंचायत के 1100, लकेया पंचायत के 1100, भदौली पंचायत के 800 और कुदरा पंचायत के 250 लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाता था। एक माह में जल कर 62 रुपया है। वहीं जल कर की जिम्मेवारी पंचायत के मुखिया और जलसहि्या को दिया गया था। जिसमें की लकेया पंचायत को छोड़कर अन्य तीन पंचायत के मुखिया और जलसहिद्या जल कर जमा नहीं करते थे, जिसके कारण फंड के अभाव में समय पर मशीन मरम्मत नहीं हो पा रहा है। जानकारी लेने के लिए सहिया से संपर्क किया गया। परंतु संपर्क नहीं हो सका। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर प्रखंड प्रमुख मीना देवी भी पानी टंकी का निरीक्षण की थी। वहीं निरीक्षण के बाद ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द बनवाने को लेकर मैकेनिकल इंजीनियर और जेईई से बात कर दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। बहुत ही जल्द पानी सप्लाई सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। ये बातें जेईई रतन खलखो ने कहा।

किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं दे : थाना प्रभारी

सिसई (गुमला)। सिसई थाना में बुधवार को थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह के अध्यक्षता में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्द के साथ मनाने को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया।



थाना प्रभारी ने पर्व को शांति पूर्ण तरीके से मनाने के लिए लोगों से अपील करतेहुए कहा कि जुलूस के दौरान केवल पारंपरिक अस्त्र का प्रदर्शन करना है। और किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया में ए आई का जमाना है, जिसके माध्यम से कोई भी असामाजिक तत्त्व किसी का भी फोटो लगाकर गलत संदेश वायरल कर सकता है जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ने का संभावना बढ़ जाता है। इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। और ऐसे फेक न्यूज से बचना है यदि किसी प्रकार का कोई फेक न्यूज मिलता है तो थाना को तुरन्त सूचना दें। सिसई बहुत ही शांति प्रिय जगह है और यहां पर सभी समुदाय के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगी।अंजुमन के लोगों ने बताया कि मुहर्रम का जुलूस सात जुलाई को राति में और आठ जुलाई को दिन में निकाला जाएगा।इस बैठक में बीडीओ रमेश कुमार यादव, सीओ नितेश रोशन खलखो, मुखिया शकुंतला देवी, बजरंग दल संरक्षक मुकेश श्रीवास्तव डेविड, रोहित शर्मा, अंजुमन के अध्यक्ष सलमान अली, महमूद अंसारी, उमर अंसारी , मनोज वर्मा, जीतवाहन साहु, तेजमोहन साहु एवं कई गणमान्य प्रभुजन शामिल थे।

बारिश के कारण वाहन हो रहे हैं दुर्घटना के शिकार बसिया(गुमला)। मेहमानी की रस्म अदायगी के लिए जा रहा एक परिवार आज सुबह सुबह अस्पताल के वार्ड में जा पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार खुंटी जिले के तोरपा मनातु से सिमडेगा गुटबहार की ओर जा रहे इस परिवार के निजी वाहन का टायर बसिया केमताटोली के पास ब्लास्ट कर गया। टायर के फट जाने से चालक एलवीन भेंगरा (35) सहित वाहन सवार किरण भेंगरा (52),अलगसियुस भेंगरा (50), प्रफुलित कांगडी (45), जेबियर भेंगरा (52), प्रभा किंडो (51),बिपुल भेंगरा (27), बेरोनिका तोपनो (50) और विनोद कांगाडी (50) जख्मी हो गए। इस दुर्घटना में शामिल लोगों का दुर्भाग्य यह कि मेहमानी के भोज की जगह अब उन्हें अस्पताल के वार्ड का भोजन खाना पड़ रहा है।

जिला मत्स्य कार्यालय, गढ़वा
आवश्यक सूचना
एतद् द्वारा सभी मत्स्य कृषकों को सूचित किया जाता है कि निई तकनीक Block Chain एवं National Fisheries Digital Platform (NFDP) में सभी मत्स्य कृषकों का निबंधन कराना आवश्यक है।
1.पासपोर्ट फोटो। (रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो)
2.अपना मोबाईल/माबाईल नं०
3.आधार मूल प्रति (Original)
4.बैंक पासबुक (Original)
5.पैनकार्ड (Original)
6.वोटर आई0डी0 कार्ड (Original)
7.राशन कार्ड (Original)
8.जमीन का रसीद (यदि हो तो)
9.आय प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
10.जाति प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
11.तालाब का विवरणी :- खाता, प्लॉट सं०, तालाब का जलक्षेत्र (एकड़ में)/ लैण्डमार्क/ जीओटोग्राफ फोटोग्राफ
12.तालाब किस योजना/किस
विभाग/निजी/लीज/सामुदायिक/वर्ष में बना है।
13.वंशावली/खतियान का प्रति। (यदिहो तो)
14.मकान/खाता सं० (NFDP मॅनिबंधन के लिए)
15.मत्स्य कृषक का आधार से मोबाईल नं० लिंक होना चाहिए।
सभी कृषक/बीज उत्पादक उक्त कागजात के साथ जिला मत्स्य कार्यालय, गढ़वा में उपस्थित होकर अपना निबंधन करायें। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर सम्पर्क कर सकते है।
जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह
PR 356440 Fish(25-26).D मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,गढ़वा

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, लातेहार
अतिअल्पकालिन
—: पुन: ई—निविदा से संबंधित आवश्यक सूचना —:
प्रभारी पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 655 दिनांक 10.05.2025 के द्वारा लातेहार जिला के प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावी क्षेत्र प्रखण्ड लातेहार के पंचायत भुमुर में Integrated Sports cum Knowledge Center esa Science Center का निर्माण/ अधिष्ठापन कार्य हेतु निविदा www.jharkhandtenders.gov.in पर पुन: प्रकाशित किया गया है।
संबंधित निविदादाता उक्त निविदा का विस्तृत अवलोकन www.jharkhand tenders.gov.in पर करते हुए दिनांक 12.07.2025 अपराहन 5:00 बजे तक अपना निविदा भेज सकते हैं। निर्धारित समयाधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार।
PR.NO.356419 Human Resource Development(25-26):D



संपादकीय

कट्टरपंथी बांग्लादेश के संदेश

कहा जाता है आप पड़ोसी बदल नहीं सकते पर यदि पड़ोसी बदल कर हिंसक धार्मिक कट्टरपंथी मार्ग पर चलने लगे तो मुकदर्शक बने रहने से भविष्य में खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। भारत पर मामूली बातों को लेकर हमलावार कथित बुद्धिजीवी इस मुद्दे पर चुप हैं और पड़ोसी पाकिस्तान को मोहरा बना रहा अमेरिका तो दूसरी ओर फिर शत्रु चीन दोधारी तलवार की तरह काम कर रहा है एक ओर कपड़ा उद्योग में अग्रणी बांग्लादेश की बर्बादी को हवा दे रहा है तो दूसरी ओर कट्टरपंथी शक्तियाँ परोक्ष सहायता देकर भारत को चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले में पिछले दिनों एक हिंदू महिला के साथ क्रूर दुष्कर्म और उग्रता वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने की घटना से एक बार फिर साबित हुआ है कि वहां हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले साल अमरुत में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ लश्कित हमलों में जिस तरह से तेजी आई है, और हिंसा के माहौल को दर्शाती ताना घटना में भी आरोपियों ने जिस जघनता के साथ अपराध को अंजाम दिया, वह बताता है कि अंतिम सरकार में कट्टरपंथी ताकतों को किसी प्रकार का डर ही नहीं रह गया है। अपराधियों ने हिंदू महिला के साथ हुई क्रूरता का वीडियो जिस तरह से युद्ध की ट्रॉफी वाले अंजल में डाला, कम से कम उससे तो यही जाहिर होता है। अब तक जिन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें मुख्य आरोपी फकीर अली भी शामिल है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से जुड़ा बताया जा रहा है।मामले के तूल पकड़ने के

बाद बेशक बांग्लादेश हाईकोर्ट ने वायरल वीडियो को तुरंत हटाने और पीड़िता की सुरक्षा व चिकित्सा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन घटना की एफआईआर दर्ज करने में देरी, पहले 24 घंटों के भीतर चिकित्सा जांच न कराना और पीड़िता के अधिकारों के प्रति जिस तरह का उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया गया, वह व्यवस्थागत लापरवाही का ही उदाहरण है। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए मानवाधिकार कंग्रेस (एचआरसीबीएम) की रिपोर्ट तो और भी दहलाने वाली है, जिसके अनुसार कुमिल्ला जिले में हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म का यह कोई पहला मामला नहीं है। अप्रैल के बाद से अब तक इस तरह के तेरह मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन इत्यादि की जो खबरें मिल रही हैं, उन पर प्रशासन के रवैए से तो यही पता चलता है कि बांग्लादेश में अंतिम सरकार इसे कोई मुद्दा ही नहीं मानती। यह स्थिति बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा के माहौल को दर्शाती है।गौरतलब है कि बांग्लादेश में इस वक्त आठ फौसदी से भी कम हिंदु हैं और उनकी आबादी लगातार घटती जा रही है। अंतिम सरकार पर उनकी चुपची अप्रत्याशित नहीं लगती। लेकिन जब बांग्लादेश ने दूसरा पाकिस्तान होने की टान ही ली है, तो जरूरी हो जाता है कि भारत कूटनीतिक व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को इस तरह उठाए कि बांग्लादेश पर जवाबदेही का दबाव बने।

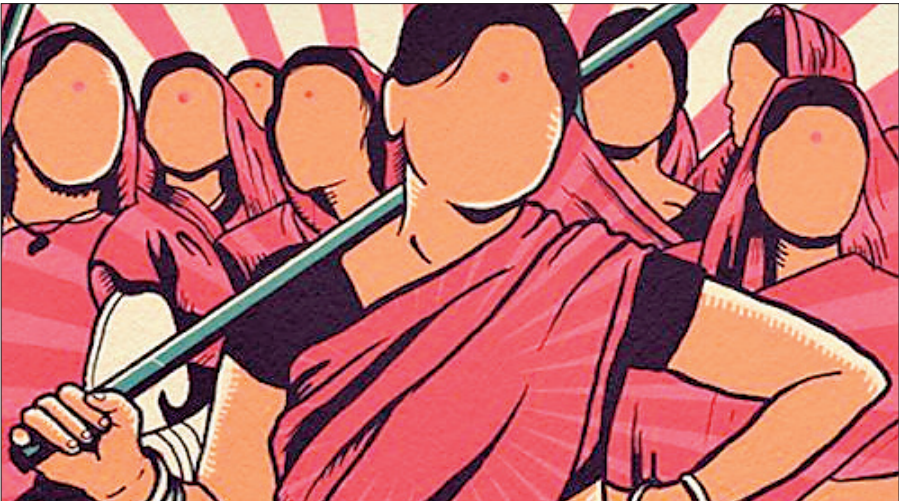


बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले में पिछले दिनों एक हिंदू महिला के साथ क्रूर दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने की घटना से एक बार फिर साबित हुआ है कि वहां हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला थमा नहीं है।

सशक्तिकरण की शुरुआत पहुंच-अधिकारों, सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच से होती है। बोते दशकों, अधिक समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त भारत का निर्माण करने पर केंद्रित मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से इस पहुंच को नए सिरे से परिभाषित किया गया है और सभी के लिए सुलभ बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस परिवर्तन में सबसे अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विजन से निर्देशित, मंत्रालय ने लाभ को अंतिम छोर तक त्वरित, पारदर्शी और कुशल तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी को व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया है। हम अक्सर कहते हैं: "सशक्त महिलाएं, सशक्त भारत।" और सशक्तिकरण की शुरुआत पहुँच - अधिकारों, सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों तक पहुँच से होनी चाहिए। आज, यह पहुँच तेजी से डिजिटल होती जा रही है। जो कभी आकांक्षायुक्त था, वह अब क्रियाशील बन चुका है -ऐसा सरकार द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसरचन्दा, रियल-टाइम डेटा सिस्टम और उत्तरदायी शासन पर जोर दिए जाने की बदौलत संभव हुआ है।

मंत्रालय ने देखरेख, संरक्षण और सशक्तीकरण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करते हुए - पोषण, शिक्षा, कानूनी सुरक्षा और आवश्यक अधिकारों तक पहुँच को मजबूत किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं और बच्चे न केवल अधिक स्वस्थ, अधिक सुरक्षित जीवन जी सकें, बल्कि वे आत्मविश्वासी नेतृत्वकर्ता और अमृत काल के परिवर्तनकर्ता के रूप में भी उभर सकें।

जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सटीक रूप से कहा है, "मैं प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के साधन के रूप में तथा आशा और अवसर के बीच की दूरी को पाटने वाले उपकरण के रूप में देखता हूँ।" इस लोकाचार ने मैनुअल प्रक्रियाओं से लेकर रियल-टाइम डैशबोर्ड तक, असंबद्ध योजनाओं से लेकर एकीकृत प्लेटफॉर्म तक हमारे परिवर्तन का मार्गदर्शन किया है। इस परिवर्तन की आधारशिला सक्षम आंगनवाड़ी पहल है। भारत भर में 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए निरूपित यह कार्यक्रम बाल्यावस्था देखरेख और विकास की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पोषण, स्वास्थ्य सेवा और पूर्व-विद्यालयी शिक्षा सेवाओं की ज्यादा प्रभावी प्रदायगी संभव बनाते हुए इन केंद्रों को स्मार्ट ईंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइस और नए-नए लर्निंग टूल्स के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। देश भर में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पोषण ट्रैकर के साथ एकीकृत करने से रियल-टाइम डेटा एंट्री, कार्य निष्पादन की निगरानी और साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो पाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और



व्यापक प्रशिक्षण से लैस करके, यह पहल अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करती है। यह 2014 से पहले मौजूद मैनुअल रिकॉर्ड-कीपिंग और डेटा क्लाइंड सपोर्ट से एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है।

एक दशक पहले, आईसीडीएस प्रणाली असंबद्ध डेटा, विलंबित प्रतिक्रियाओं और रियल-टाइम ट्रैकिंग की कमी से दबी हुई थी। पोषण ट्रैकर ने - पोषण सेवा प्रदायगी में सटीकता, दक्षता और जवाबदेही की शुरुआत कर इस परिदृश्य को बदल दिया है। 10.14 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अब इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं- जिनमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, छह साल से कम उम्र के बच्चे और किशोरियाँ शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म विकास की निगरानी और पूरक पोषण प्रदायगी पर रियल-टाइम अपडेट को सक्षम बनाते हुए समय पर हस्तक्षेप और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण सुनिश्चित करता है। डिजिटल रूप से सशक्त सामुदायिक केंद्रों के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों की नए सिरे से परिकल्पना कर, शहरी

ग्रामीण विभाजन को पाटते हुए- पोषण ट्रैकर महत्वपूर्ण रूप से स्वस्थ भारत, सुपोषित भारत के राष्ट्रीय विजन को आगे बढ़ा रहा है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (2025) से सम्मानित यह मंच 'पोषण भी पढ़ाई भी' का भी समर्थन करता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करते हुए विकसित भारत के अमृत काल में समग्र देखभाल को बढ़ावा दे रहा है। पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) में पारदर्शिता को और मजबूत करने तथा लीकेज कम करने के लिए एक फेशियल रिकॉमिन्शन सिस्टम शुरू किया गया है। इस डिलिवरी तंत्र को सुरक्षित, सटीक और सम्मानजनक बनाते हुए यह सुनिश्चित करता

है कि पोषण सहायता केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले। प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यह मंत्रालय पोषण से बढ़कर, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित कर रहा है। शो-बॉक्स पोर्टल हर महिला को, चाहे वह किसी भी रोजगार की स्थिति में हो या संतुष्टि या असंतुष्टि, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हो, पांश अधिनियम के तहत उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए सिंगल-विंडो एक्सेस प्रदान करता है - जिससे ऑनलाइन निवारण और ट्रैकिंग संभव हो पाती है। इस बीच, मिशन शक्ति डैशबोर्ड एंड मोबाइल ऐप संकट से घिरी महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करता है, उन्हें निकटतम वन स्टॉप सेंटर से जोड़ता है - जो अब लगभग हर जिले में चालू है। ये कदम इस बात का उदाहरण हैं कि तकनीक का उपयोग न केवल दक्षता के लिए, बल्कि न्याय, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भी किया जा रहा है। एक दशक पहले, मातृत्व लाभ की निगरानी करना मुश्किल था और इसमें देरी होती थी। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की शुरुआत की है - जो मातृ कल्याण की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव है।

पीएमएमवीवाई नियम, 2022 के तहत, गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि मिलती है। मिशन शक्ति के तहत, अगर दूसरा बच्चा लड़की है, तो - बेटियों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देते हुए लाभ की राशि 6,000 रुपये तक बढ़ जाती है। कामज रहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से वितरित, शुरुआत से अब तक 4 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों तक 1,9000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुँच चुकी है। पीएमएमवीवाई - आधार-आधारित प्रमाणिकरण, मोबाइल-आधारित पंजीकरण, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर सहायता और रियल-टाइम डैशबोर्ड का लाभ उठाते हुए एक पूर्णतः डिजिटल कार्यक्रम है। एक समर्पित शिकायत निवारण मॉड्यूल तथा पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला नागरिकों से संबंधित पोर्टल है - जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

झरिया की जलती धरती : कोयले की आग में झुलसती जिंदगी और पर्यावरण

खूबसूरत राज्य झारखंड को प्रकृति ने बड़ी कृपित से गढ़ा है। यहां की हरियाली, पहाड़, झरने और नदियाँ किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन यह राज्य केवल अपनी प्राकृतिक संपन्नता के लिए ही नहीं, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले कोयला भंडारों के लिए भी प्रसिद्ध है। झारखंड में देश का लगभग 19 प्रतिशत कोयला है, और जियोलाॅजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यहां करीब 86 हजार मिलियन टन कोयले का भंडार मौजूद है, जो अगले 70 वर्षों तक देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। सुनने में यह

आपकी बात



मिथलेश दास

संरक्षण, या पर्यावरण की कोई परवाह नहीं की गई। अवैज्ञानिक और लापरवाह खनन ने आग को जन्म दिया और झरिया को एक पर्यावरणीय नरक में बदल दिया। आज झरिया के कई इलाके ऐसे हैं, जहाँ धुएँ के गुबार और जहरीली हवा आम बात है। आग के कारण भूमि का क्षरण जारी है, ज़मीन धँसती जा रही है और घरों में दरारें पड़ती जा रही हैं। कभी-कभी अचानक भूधंसन से गोफ बनते हैं, जिनमें इंसान समा जाते हैं। यह सब इतना आम हो चला है कि लोग मौत को जीवन का हिस्सा मानकर जीने को विवश हैं। पुरे देश को ऊर्जा देने वाला झरिया, खुद अंधेरे और असुरक्षा में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग रोज़ाना ज़मीन के नीचे की आग और ऊपर की वैसेली हवा के बीच जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद, कई लोग यह क्षेत्र छोड़कर जाना नहीं चाहते। एक वजह है- रोज़गार। झरिया न केवल एक खनन क्षेत्र है, बल्कि एक व्यावसायिक केंद्र भी है। यहाँ छोटे-बड़े कारोबारी, खोमचे वाले, मजदूर और दुकानदार अपनी आजीविका चलाते हैं। बेलगढ़िया टाउनशिप

में जिन लोगों को पुनर्वास के तहत घर मिले, वे कुछ समय बाद फिर से झरिया लौट आए, क्योंकि वहां रहने के लिए घर तो था, लेकिन रोज़गार और मूलभूत सुविधाएँ नहीं थीं। झरिया में भूमिगत आग से सबसे बड़ा असर पर्यावरण और मानवीय जीवन पर पड़ा है। आग से निकलती जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, न केवल हवा को जहरीला बना रही हैं, बल्कि सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियाँ जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और ल्वचा रोग यहाँ आम हो गए हैं। क्षेत्र में तापमान असामान्य रूप से बढ़ा है, मिट्टी बंजर हो चुकी है और भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यह सब मिलकर झरिया को एक जीवित पर्यावरणीय आपदा क्षेत्र बना चुका है। लेकिन यह आग केवल कोयले और पर्यावरण तक सीमित नहीं, यह लोगों के जीवन में भी धधकती है। 24 मई 2017 को झरिया के ईर्झा चौक (फुलारीबाग) क्षेत्र में एक भयावह हादसा हुआ, जब एक गैराज मिस्री बबलू गढ़ी और उनका 14 वर्षीय पुत्र रहीम अचानक ज़मीन धँसने से उसमें समा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ज़मीन धंसते ही जोरदार गैस रिसाव हुआ और अगल-बगल की ज़मीन भी अत्यंत गर्म हो गई। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस भयंकर स्थिति का संकेत है जिसमें झरिया के लोग हर दिन जी रहे हैं। वर्ष 2018 से आरएसपी कॉलेज, झरिया को भूमिगत आग के खतरे के कारण अस्थायी रूप से झरिया से स्थानांतरित कर बेलगढ़िया टाउनशिप में संचालित किया जा रहा है। यह एक शिक्षण संस्थान के विस्थापन की दुर्लभ और चिंताजनक स्थिति है, जो बताता है कि झरिया की आग अब केवल घरों को ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था को भी जला रही है। और इतना ही नहीं, 2020 में झरिया क्षेत्र के स्कूलों का बंद होना इन त्रासदियों का जीवंत प्रमाण है।

झरिया मास्टर प्लान, जिसे एशिया की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना कहा जाता है, 2009 में प्रारंभ हुआ था और इसका लक्ष्य था कि 2021 तक झरिया के अर्धनप्रभावित क्षेत्रों के सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन आज भी पुनर्वास का कार्य अधूरा है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण के तहत अब तक केवल आंशिक सफलता मिली है। लगभग 32 हजार रैयत और एक लाख से अधिक गैर-रैयत, जो किसी न किसी रूप में झरिया की ज़मीन और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, पुनर्वास के प्रति असमंजस में हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

फेसबुक वॉल से



एक्स से



आज का दोहा

राजनीति कुछ खास की, खास हंग की नाव।

देश देश में बिक रही, लोकतंत्र के भाव।।

सोमदत्त शर्मा, गाजियाबाद (उ.प्र.)

रचना भेजिए

समाचारों के संबंध में शिकायत या इस पेज के लिए

आर्टिकल कृपया भेजें artical.rnmail@gmail.com

कॉल/व्हाट्सएप 8292553444

संपादक

विश्व गुरु का संकल्प : आठ दिनों में पांच महादेशों को जोड़ता भारत

जब विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी साहसिक और दूरदर्शी यात्रा पर निकले हैं, जो ग्लोबल साउथ और विश्व मंच पर भारत को एक सशक्त, अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। यह आठ दिवसीय यात्रा—घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, और नामीबिया—मात्र कूटनीति नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, रणनीतिक कुशलता और वैश्विक नेतृत्व की प्रबल घोषणा है। ऐसे दौर में, जब वैश्विक भू-राजनीति अनिश्चितता के भंवर में उलझी है और अमेरिकी नीतियां नए वैश्विक समीकरण गढ़ रही हैं, यह यात्रा भारत को एक विश्वसनीय, प्रभावशाली और प्रेरक शक्ति के रूप में उभारती है। यह दौरा भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा हितों को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ जोड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास है, जो भारत की वैश्विक आवाज को और सशक्त करेगा। साथ ही, यह यात्रा भारत के 'विश्व गुरु' के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है, जो समावेशी विकास और वैश्विक एकता के प्रति अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

घाना में पहला पड़ाव भारत के लिए पश्चिमी अफ्रीका के साथ एक अभूतपूर्व साझेदारी का स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा भारत-घाना संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। 2024-25 में भारत घाना का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा, जिसमें घाना से भारत के आयात का 70% से अधिक हिस्सा सोने का है। इसके साथ ही, भारत ने घाना में डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है, जिसने घाना की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नया बल दिया है। रक्षा सहयोग के तहत भारत द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण और अत्याधुनिक उपकरण, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में रणनीतिक निवेश, इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह दौरा अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की मित्रता को एक नया आलोक प्रदान करेगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक, परिवर्तनकारी साझेदारी का मजबूत आधार रचेगा। 3-4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो की धरती पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल की 40-45% आबादी के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बंधनों का

एक सशक्त, आत्मीय और प्रेरक उत्सव रचेगे।

1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा, भारतीय प्रवासियों की 180 वर्षों की गौरवमयी विरासत को एक नया आलोक प्रदान करती है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच 341.61 मिलियन डॉलर का व्यापार इस रिश्ते की जीवंतता और गहराई को रंगीन कैनवास पर उकेरता है। भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो को नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग दिया है, जिसमें सौर ऊर्जा की क्रांतिकारी परियोजनाएं और डिजिटल शिक्षा की नवोन्मेषी पहल शामिल हैं। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए और राष्ट्रपति क्रिस्टीन काराला केंगालू प्रदान बिसेसर के साथ विचार-विमर्श में, पीएम मोदी कैरिबियाई क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली उपस्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। यह दौरा सांस्कृतिक एकता, व्यापारिक गतिशीलता और तकनीकी सहयोग का एक अनुपम समन्वय प्रस्तुत करता है, जो भारत के सांपट पावर को वैश्विक मंच पर एक चमकते सितारे की तरह देदीयमान बनाएगा।

4-5 जुलाई को अर्जेंटीना की धरती पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ रक्षा, कृषि, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को एक नई, गतिशील दिशा देंगे। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा, लिथियम जैसे रणनीतिक खनिजों में साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लिथियम, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति और हरित ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का आधार है, और अर्जेंटीना विश्व के सबसे विशाल लिथियम भंडारों का धनी है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार, जो सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर केंद्रित है, 2.5 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है, जो भारत को दक्षिण अमेरिका में एक प्रमुख व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

कलम का अपमान पदवी का सम्मान

ज्ञानपुर के बीचों-बीच, जर्जर सी, पर भव्य दिखने वाली इमारत, 'ज्ञानपुर साहित्य संगम' का पता देती थी। बाहर से तो उसकी रंगत, दीवारों पर उकेरी गई कविताओं की कंदलें, और नीम के पेड़ के नीचे बैठे कबूतरों का गुटरगूँ, किसी गुरुकुल का भ्रम पैदा कर सकता था। मगर अंदर का हाल पृष्ठिए तो 'गिरा अर्थ जल बीचि सगं' वाला तुलसी का प्रेम, किसी 'कोका कोला और भेलपुरी' के संगम में बदल चुका था। यहां 'हिंदी' तो बस नाम भर की थी, एक 'ब्रांडिंग' के लिए, जैसे किसी दाल-रोटी के ढाबे पर 'पेटहाउस' लिखा हो। और 'साहित्य ?' अरे, साहित्य तो बेचारा कब का अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर, किसी अनजाने गँव की कच्ची राह पर निकल चुका था, जहां मोबाइल नेटवर्क भी न पहुँच सके। यहाँ तो 'साहित्य निष्कासित' कर दिया गया हो-सो हिंदी साहित्य संगम।' यह बहुब्रीहि समास का जीवंत उदाहरण था। कविराज दीनानाथ, जो अपनी कलम को अपनी साँसों से भी पवित्र मानते थे, अक्सर इस संगम के बाहर खड़े होकर एक लंबी आह भरते। उनकी कविताओं में जीवन की पीड़ा, समाज का यथार्थ और मनुष्य की आत्मा की अनकही कहानियां गुंजती थीं। पर इस संगम में, उनकी कविताओं के बोल, किसी सकारी घोषणापत्र के सामने, मच्छर की भिनभिनाहट से भी कम सुनाई पड़ते थे। वे देखते कि कैसे साहित्य के नाम पर, साहित्यकारों का ही नहीं, बल्कि उस सरस्वती का भी अपमान हो रहा है, जिसकी वंदना करके सदियों से ये मंच पवित्र किए जाते थे। उनका हृदय इस विडंबना

देश की बात



डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

को देखकर रो उठता था, जैसे कोई बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे को गलत राह पर जाते देख कराह उठे। ज्ञानपुर की गलियों में कविराज दीनानाथ के लिए सम्मान था, पर 'ज्ञानपुर साहित्य संगम' में वे बस एक 'फालतू' आदमी थे, जिसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। संगम में एक भव्य 'अभिनेदन समारोह' की घोषणा हुई। शहर में खबर फैलते ही, साहित्य प्रेमियों की आँखें चमक उठीं। "वाह! आहूँ! आहूँ! किसी सच्चे साहित्यकार को सम्मान मिलेगा!" कोई बोला। "कहीं कविराज दीनानाथ ही तो नहीं?" किसी के मुह से अनायास ही निकल गया। कल्पना कीजिए, एक साहित्यकार, जिसने अपनी पूरी उम्र, अपनी कलम के बल पर, फटेहाली और गुरबत में गुजारी हो, उसे इस उम्र में मान-सम्मान मिल जाए तो उसका हृदय कैसे प्रफुल्लित होगा? दीनानाथ जी के शिष्यों ने भी अपने गुरु की ओर आशा भरी नज़रों से देखा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

अलग बात



प्रो. आरुण जैन

रूस से तेल खरीदने वालों पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी में है यूएस

इसका भी इलाज हूढ़ लेंगे : जयशंकर

ब्यूरो

नई दिल्ली । विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की वाशिंगटन में हुई प्रेस वार्ता में भारत-अमेरिका संबंधों की परिपक्वता, वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका और समसामयिक अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने भारत की विश्व नीति की प्राथमिकताओं, सामरिक संतुलन, व्यापारिक संबंधों और ग्लोबल साउथ के साथ भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती से रेखांकित किया साथ ही यह भी बताया कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका जो भारी भरकम टैक्स लगाने की तैयारी में है उसको लेकर भारत का रुख क्या है। प्रेस वार्ता के दौरान जयशंकर ने भारत पाकिस्तान, जयशंकर ने संबंधों और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से युद्धविराम कराने के बार-बार किये जा रहे दावे के संबंध में भी सवालों के जवाब दिये। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित

‘लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले की मौत पर मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं बीमा कंपनी’ ब्यूरो

नई दिल्ली। यदि आप अपना इंश्योरेंस करए हैं , लेकिन कोई वाहन लापरवाही या स्टंटबाजी करते हुए चला रहे हैं , गलत साइट से चला रहे हैं , उस दौरान दुर्घटना हुई और आप दिवंगत हो गये तो इंश्योरेंस कंपनीयां आपके परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व आर. महादेवन की बेंच ने एक मामले में यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई ड्राइवर खुद की गलती से मर जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनियां उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस बेंच ने एक ऐसे व्यक्ति के परिवार को राहत देने से मना कर दिया जिसकी मौत तेज गति से गाड़ी चलाने के दौरान हुई थी। गाड़ी चलाते समय उसने लापरवाही बरती थी, जिसके कारण गाड़ी पलट गई थी। मृतक के परिवार ने इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की मौत उसकी अपनी गलती से होती है, तो उसके परिवार वाले इंश्योरेंस का पैसा नहीं मांग सकते।सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पिछले साल 23 नवंबर के फैसले को खी ठहराया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया था। 18 जून 2014 को एन.एस. रविशा नान का एक व्यक्ति अपनी फिफ्ट लीनिगा कार चला रहा था। उसके साथ उसके पिता, बहन और उसके बच्चे भी थे। रविशा तेज गति से गाड़ी चला रहा था और उसने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा। उसने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क पर पलट गई। रविशा को इस हादसे में गंभीर चोट लगा और उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी, बेटे व माता-पिता ने 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि रविशा एक सफल ठेकेदार था और वह हर महीने 3 लाख रुपये कमाता था। पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि यह दुर्घटना रविशा की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने परिवार के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। रविशा के परिवार ने कहा कि दुर्घटना ठायर फटने के कारण हुई। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब मृतक के कानूनी प्रतिनिधि दावा करते हैं, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि मृतक खुद अपनी लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं था। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि मृतक पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ताकि बीमा कंपनी कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। कोर्ट ने आगे कहा, “इस मामले में, यह माना गया है कि दुर्घटना मृतक की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। वह खुद ही अपनी मौत का कारण बना। इसलिए, कानूनी उत्तराधिकारी उसकी मौत के लिए कोई मुआवजा नहीं मांग सकते।

रूस से भारत का कच्चा तेल आयात 10 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर



नहीं हैं, बल्कि यह तकनीकी सहयोग, रक्षा विनिर्माण, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार जैसे विविध क्षेत्रों में विस्तार पा चुके हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच साझा मूल्य और पारस्परिक सम्मान इस रिश्ते की आधारशिला है। प्रेस वार्ता में एक प्रमुख बिंदु यह रहा कि भारत साउथ के हितों की प्रभावी ढंग से वकालत कर रहा है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन विकासशील देशों के लिए भी बोल रहा है जिन्हें अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अनदेखा कर दिया जाता है। भारत की जी20 अध्यक्षता के

बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन के तरीके से भाजपा के सहयोगी दल भी नाराज

ब्यूरो

नई दिल्ली। बिहार में 21 अक्टूबर से 20 नवम्बर तक 6 चरणों में चुनाव और 24 नवंबर को परिणाम घोषित होने की चर्चा हो रही है। और बिहार में हालत यह है कि वहाँ इसे लेकर घमासान हो रहा है कि चुनाव आयोग वहां पर वोटर लिस्ट का सत्यापन लोकसभा चुनाव के बाद से नहीं करारक अब संधान सभा चुनाव जब सिर पर आ गया तो इतनी जल्दी बाजी व कम समय में क्यों करा रहा है? क्या यह तथाकथित महाराष्ट्र व हरियाणा जैसा कुछ करने के लिए हो रहा है ? इसको लेकर विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की ,लेकिन बिहार में भाजपा के सहयोगी दल हैं उनमें से चिराग पासवान सहित अन्य कई सहयोगी दल के नेता भी पेशान हैं।विपक्ष ने सवाल उठाया है कि वोटर लिस्ट के सत्यापन का जो काम पिछले 22 सालों में नहीं हुआ उसे बिहार में बिहार विस चुनाव के इतने कम समय में अब क्यों किया जा रहा है ? और उसके लिए लोगों से जिस तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, अब जब चुनाव में कुछ ही माह का समय है, ऐसे में लोगों को उन दस्तावेज को देने में मुश्किल होगी और इससे बिहार में 2 से 3 करोड़ मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे।इसमें ज्यादातर मतदाता विपक्षी दलों व निराग पासवान जैसे भाजपा के सहयोगी दलों के हो सकते हैं। कुछ सीटों पर भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू के भी मतदाता हो सकते हैं। इधर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या 2003 में मतदाता सूची



- कहने लगे- ये गरीबों, दलितों, आदिवासियों व ओबीसी समुदाय को वोट डालने से वंचित करने की साजिश
- मतदाता सूची का सत्यापन 25 जून को शुरू हुआ, 25 जुलाई तक पूरा किया जाना है, हर हालत में मात्र एक माह में

क आतम।रवाजन क बाद स कराए गए सभी चुनाव गलत थे? इसी तरह तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बन गया है। हालत यह है कि अकेले बातचीत में भाजपा, जदयू व लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कई नेताओं ने इसे लेकर संदेह बताया कि क्या इतने कम समय में चुनाव आयोग यह काम पूरा कर पाएगा ? मालूम हो कि मतदाता सूची के सत्यापन का यह काम 25 जून को शुरू हुआ था और इसे 25 जुलाई तक पूरा किया जाना है यानि हर हालत में मात्र एक माह में । इन नेताओं ने राज्य में साक्षरता, गरीबी व प्रशासनिक इंतजामों को लेकर बात की और कहा कि कई लोगों विशेषकर गरीबों के पास जन्म तिथि व जन्म स्थान के प्रमाण

के रूप में चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज में से कोई भी नहीं होगा। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक नेता का कहना है कि क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने से वोटर को कोई सरकारी फायदा मिलता नहीं है, इसलिए बिहार के मतदाता भी इसके लिए अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करेंगे और उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को ही निभानी पड़ेगी। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने अपने निर्देशों में कहा है कि हर मतदाता को व्यक्तिगत गणना फॉर्म जमा करना जरूरी है। 1987 के बाद जन्मे और 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल होने वाले लोगों को जन्मतिथि प्रमाण पत्र , पासपोर्ट या किसी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के मार्फत अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा।चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण देने के लिए जुलाई 1987 की कट ऑफ तिथि निर्धारित की है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2000 में राज्य में केवल 1.19 लाख जन्म पंजीकृत हुए थे, जो उस साल बिहार में अनुमानित हुए कुल जन्म का मात्र 3.7% था जबकि तब राष्ट्रीय औसत 56% था।2001 की जनगणना के अनुसार, 1 मार्च 2001 को बिहार को आबादी 8.3 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 10.4 करोड़ हो गई।यानी राज्य की आबादी में 2.11 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस दौरान बिहार 73.91 लाख ही जन्म पंजीकृत हुए।

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2011 के फोन-टैपिंग आदेश को रद्द कर दिया

हर बार नहीं किया जा सकता फोन टैप, सीबीआई को फटकार, केंद्र को झटका

ब्यूरो

नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2011 के फोन-टैपिंग आदेश को रद्द कर दिया। इसमें कहा गया कि निगरानी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है। अपने फैसले में जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि आज के कानून के अनुसार अपराधों का पता लगाने के उद्देश्य से गुप्त ऑपरेशन या गुप्त स्थितियों के उद्देश्य से टेलीफोन पर बातचीत या संदेशों की टैपिंग की अनुमति नहीं है। 94 पेज के आदेश में अदालत ने कहा कि फोन टैपिंग इस तरह से किसी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, जब तक कि इसे कानून द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता है। यह मामला याचिकाकर्ता पी किशोर (एवरॉन एजुकेशन लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक) से संबंधित है, जिन्होंने 12 अगस्त, 2011 के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419-A के तहत उनके मोबाइल फ़ोन को इंटरसेप्शन के लिए अधिकृत किया गया था।



निजता का अधिकार 2017 में के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद मौलिक अधिकार बन गया है

एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी को कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत से जुड़ी सीबीआई जांच के सिलसिले में निगरानी का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि निगरानी के लिए राज्य का औचित्य (भ्रष्टाचार का पता लगाने की आवश्यकता) फोन टैपिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण करने के लिए आवश्यक कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता है। जस्टिस वेंकटेश ने 1997 के पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए लिखा, “मौजूदा मामले में आरोपित (चुनौती के तहत) आदेश न तो सार्वजनिक आपातकाल के दायरे में आता है और न ही सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, जैसा कि पीयूसीएल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया है।” जस्टिस

ने कहा कि निजता का अधिकार 2017 में के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद मौलिक अधिकार बन गया है। जस्टिस ने कहा, “मामले के तथ्य बताते हैं कि यह एक गुप्त ऑपरेशन या अपराध का पता लगाने के लिए एक गुप्त स्थिति थी, जो किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं होगी। वर्तमान कानून के अनुसार इस तरह की स्थिति अधिनियम की धारा 5(2) के दायरे में नहीं आती है, जैसा कि पीयूसीएल में सुप्रीम कोर्ट व्याख्या की गई है। इसे एस पुट्टस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंजूरी दी है।” अदालत ने उन शर्तों को भी निर्धारित किया, जिनके तहत फोन टैपिंग वैलिड रूप से की जा सकती है। यह सार्वजनिक आपातकाल के दौरान या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में की जा सकती है।

नई दिल्ली। बौद्ध धर्म गुरु 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो 6 जुलाई को 90 वर्ष के हो जाएंगे। दलाई लामा अपने पुनर्जन्म पर एक बयान देंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कैबिनेट के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर समर्थोंग रिनपोछे और सीटीए के सिक्कोंग या राजनीतिक नेता पेनपा त्सेंरिंग उनका संदेश पढ़ेंगे। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई, 1935 को उत्तर-पूर्वी तिब्बत (अब चीन के किंघाई प्रांत) के तक्त्सेर नामक गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्हें 13वें दलाई लामा थुबेतन ग्यात्सो के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया था। चीन में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के एक साल बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर आक्रमण किया। 1951 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया और मार्च 1959 में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह को चीनी सैनिकों ने कुचल दिया।मार्च 1959 में दलाई लामा अपने अनुयायियों के एक समूह के साथ ल्हासा से भाग निकले और अरुणाचल प्रदेश के खेंजीमाने में भारत में प्रवेश किया। 1960 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उन्हें धर्मशाला के मैकलोडगंज में बसाया, जहां निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की गई। 14 मार्च 2011 को दलाई लामा ने तिब्बती पीपुल्स डेप्युटीज की असेंबली को पत्र लिखा, जिसे निर्वासित तिब्बती संसद के रूप में जाना जाता है। निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता को राजनीतिक सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण उस वर्ष 29 मई को हुआ, जिससे 368 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई। इस दौरान दलाई लामा तिब्बतियों के आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों प्रमुख थे।दलाई लामा (जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘ज्ञान का सागर, अवलोकितेश्वर या चैनेरजिंग) और इन्हें तिब्बत के संरक्षक संत का अवतार माना जाता है। बोधिसत्व वे व्यक्ति हैं जो बुद्ध बनने के मार्ग पर हैं, लेकिन जो स्वयं निर्वाण में प्रवेश करने से पहले अन्य संवेदनशील प्राणियों की मुक्ति को प्राथमिकता देते हैं।दलाई लामा की संस्था तिब्बती बौद्ध धर्म में तुलुक अवधारणा का हिस्सा है, जिसमें आध्यात्मिक गुरुओं को उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म दिया जाता है। ऐसा

लिंडसे ग्राहम के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चर्चाओं को साझा कर दिया है। हम आपको बता दें कि ग्राहम ही उस विधेयक को लाये हैं जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों— विशेषकर भारत और चीन पर 500% तक आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। जयशंकर ने कहा, “हमने अपनी चिंताएं और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हित उनके समक्ष रखे हैं। यदि यह स्थिति आती है, तो हम उसका समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे।” हम आपको बता दें कि इस विधेयक को ट्रंप प्रशासन का भी समर्थन प्राप्त है।यह विधेयक यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है।

सिंधु जल संधि पर भारत के ऐक्शन से पाक में बढ़ा खौफ

इस्लामाबाद । पिछले सप्ताह स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में दिए गए फैसले के बाद, पाकिस्तान अब भारत से द्विपक्षीय जल-बंटवारे संधि के कार्यान्वयन को फिर से शुरू करने का आह्वान कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फैसले से इस्लामाबाद की कानूनी स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन नई दिल्ली द्वारा संधि का पालन करने की संभावना नहीं है। 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर अधिकार देती है, जबकि भारत को रावी, सतलुज और ब्यास नदियों पर नियंत्रण प्रदान करती है। अप्रैल के महीने में प्रधान कश्मीर के पहलुगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को निरस्त करने की घोषणा कर दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय से रामदेव के पंतजलि आयुर्वेद को झटका

डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ टीवी विज्ञापन दिखाने पर रोक

ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु से धंधा गुरु बन गये रामदेव की कंपनी पंतजलि आयुर्वेद को झटका देते हुए पंतजलि को डाबर इंडिया के च्यवनप्राश उत्पादों के विरुद्ध टीवी पर कोई भी विज्ञापन दिखाने से रोक दिया है। डाबर ने कोर्ट में कहा था कि पंतजलि के विज्ञापन उनके उत्पाद को बदनाम कर रहे हैं।कोर्ट ने डाबर की याचिका पर पंतजलि को फ़ौरन ऐसे विज्ञापन दिखाने से मना कर दिया है।इस मामले की सुनवाई बीते 24 दिसंबर को शुरू हुई थी। तब कोर्ट ने

ब्यूरो

नई दिल्ली। बौद्ध धर्म गुरु 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो 6 जुलाई को 90 वर्ष के हो जाएंगे। दलाई लामा अपने पुनर्जन्म पर एक बयान देंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कैबिनेट के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर समर्थोंग रिनपोछे और सीटीए के सिक्कोंग या राजनीतिक नेता पेनपा त्सेंरिंग उनका संदेश पढ़ेंगे। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई, 1935 को उत्तर-पूर्वी तिब्बत (अब चीन के किंघाई प्रांत) के तक्त्सेर नामक गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्हें 13वें दलाई लामा थुबेतन ग्यात्सो के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया था। चीन में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के एक साल बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर आक्रमण किया। 1951 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया और मार्च 1959 में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह को चीनी सैनिकों ने कुचल दिया।मार्च 1959 में दलाई लामा अपने अनुयायियों के एक समूह के साथ ल्हासा से भाग निकले और अरुणाचल प्रदेश के खेंजीमाने में भारत में प्रवेश किया। 1960 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उन्हें धर्मशाला के मैकलोडगंज में बसाया, जहां निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की गई। 14 मार्च 2011 को दलाई लामा ने तिब्बती पीपुल्स डेप्युटीज की असेंबली को पत्र लिखा, जिसे निर्वासित तिब्बती संसद के रूप में जाना जाता है। निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता को राजनीतिक सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण उस वर्ष 29 मई को हुआ, जिससे 368 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई। इस दौरान दलाई लामा तिब्बतियों के आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों प्रमुख थे।दलाई लामा (जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘ज्ञान का सागर, अवलोकितेश्वर या चैनेरजिंग) और इन्हें तिब्बत के संरक्षक संत का अवतार माना जाता है। बोधिसत्व वे व्यक्ति हैं जो बुद्ध बनने के मार्ग पर हैं, लेकिन जो स्वयं निर्वाण में प्रवेश करने से पहले अन्य संवेदनशील प्राणियों की मुक्ति को प्राथमिकता देते हैं।दलाई लामा की संस्था तिब्बती बौद्ध धर्म में तुलुक अवधारणा का हिस्सा है, जिसमें आध्यात्मिक गुरुओं को उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म दिया जाता है। ऐसा

लिंडसे ग्राहम के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चर्चाओं को साझा कर दिया है। हम आपको बता दें कि ग्राहम ही उस विधेयक को लाये हैं जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों— विशेषकर भारत और चीन पर 500% तक आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। जयशंकर ने कहा, “हमने अपनी चिंताएं और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हित उनके समक्ष रखे हैं। यदि यह स्थिति आती है, तो हम उसका समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे।” हम आपको बता दें कि इस विधेयक को ट्रंप प्रशासन का भी समर्थन प्राप्त है।यह विधेयक यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है।



- अपनी पुस्तक वॉयस फॉर द वॉयसलेस में दलाई लामा ने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा
- चीन ने 2007 में आदेश दिया कि कोई भी समूह या व्यक्ति आत्मा की खोज व पहचान से संबंधित गतिविधियां नहीं कर सकता है, दलाई लामा का चयन करने के लिए गोल्डन अर्न विधि नामक लॉटरी की व्यवस्था की गई

इसलिए ताकि उनका शिक्षाओं को संरक्षित किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। पहले दलाई लामा गेदुन ड्रुपा का जन्म 1391 में हुआ था। वंश के पांचवें लोबसंग ग्यात्सो (1617-82) से शुरू होकर, दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता दोनों बन गए। वर्तमान दलाई लामा को 1939 में एक खोज दल द्वारा खोजा गया था। 13वें दलाई लामा थुप्टेन ग्यात्सो के 1933 में निधन के छह साल बाद उन्हें खोजा गया। पुनर्जन्म को कई संकेतों से पहचाना गया, जिसमें एक वरिष्ठ भिक्षु को दिखाई गई वृष्टि भी शामिल थी।

1940 में छोटे बालक को ल्हासा के पोताला पैलेस में ले जाया गया और आधिकारिक रूप से सिंहासन पर बैठाया गया। 1969 से ही दलाई लामा कहते रहे हैं कि उनके पुनर्जन्म को मान्यता दी जाए या नहीं, यह तिब्बती लोगों, मंगोलों और हिमालयी क्षेत्र के लोगों को तय करना है। 24 सितंबर 2011 को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, “जब मैं लगभग 90 साल का हो जाऊंगा तो मैं तिब्बती बौद्ध परंपराओं के उच्च लामाओं, तिब्बती जनता और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करने वाले अन्य संबंधित लोगों से सलाह लूंगा और इस बात का पुनर्मूल्यांकन करूंगा कि दलाई लामा की संस्था को जारी रखना चाहिए या नहीं। उसके

दिल्ली उच्च न्यायालय से रामदेव के पंतजलि आयुर्वेद को झटका

डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ टीवी विज्ञापन दिखाने पर रोक

- पंतजलि अपने च्यवनप्राश को 51 से ज्यादा जड़ी-बूटियों से बना हुआ बता रहा है जबकि उसमें सिर्फ 47 जड़ी-बूटियां ही हैं**

पंतजलि आयुर्वेद को नोटिस भेजा था। डाबर ने न्यायालय को बताया कि नोटिस मिलने के बाद भी पंतजलि आयुर्वेद ने पिछले कुछ सप्ताह में 6,182 बार विज्ञापन दिखाए। डाबर का कहना है कि इन विज्ञापनों में गलत जानकारी दी जा रही है। पंतजलि अपने प्रोडक्ट को 51 से ज्यादा जड़ी-बूटियों से बना हुआ बता रहा है, जबकि उसमें सिर्फ 47 जड़ी-बूटियां ही हैं। डाबर का कहना है कि पंतजलि

आधार पर हम कोई फैसला लेंगे।” इस बयान की वजह से ही दलाई लामा का आने वाला जन्मदिन 6 जुलाई को महत्वपूर्ण हो गया है, जब वे 90 साल के हो जाएंगे। बयान में कहा गया है कि यदि यह तय किया जाता है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म जारी रहना चाहिए और 15वें दलाई लामा को मान्यता दिए जाने की जरूरत है, तो ऐसा करने को जिम्मेदारी मुख्य रूप से दलाई लामा के गादेन फोडरंग ट्रस्ट के संबंधित अधिकारियों पर होगी।बीते सोमवार को दलाई लामा ने कहा, “कुछ ऐसा ढांचा होगा जिसके भीतर हम दलाई लामाओं की संस्था को जारी रखने के बारे में बात कर सकते हैं।” उधर चीन है कि 14वें दलाई लामा को विभाजनकारी, देशद्रोही और निर्वासित के रूप में निंदा करता है, जिसे तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है।लेकिन अपने 2011 के बयान में दलाई लामा ने कहा था कि उनका पुनर्जन्म एक स्वतंत्र देश में होना चाहिए, न कि चीनी नियंत्रण में। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी सरकार द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुने गए पुनर्जन्म को कोई मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इस मार्च में प्रकाशित अपनी पुस्तक वॉयस फॉर द वॉयसलेस में दलाई लामा ने कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। तिब्बतियों में यह डर है कि जैसे-जैसे दलाई लामा बड़े होते जाएंगे, चीन अपनी पसंद के उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकता है, और इसका इस्तेमाल तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए कर सकता है। उधर 2004 में चीनी सरकार ने दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले धार्मिक मामलों के नियमों को समाप्त कर दिया। चीन ने 2007 में आदेश दिया कि कोई भी समूह या व्यक्ति आत्मा की खोज और पहचान से संबंधित गतिविधियां नहीं कर सकता है। दलाई लामा का चयन करने के लिए गोल्डन अर्न विधि नामक लॉटरी की व्यवस्था की गई। 2015 में तिब्बती जातीयता के एक सेवानिवृत्त चीनी राजनीतिज्ञ और तिब्बत की पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष पखा चोलिंग ने दलाई लामा के इस आग्रह पर आपत्ति जताई कि किसी भी सरकार को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अगले दलाई लामा को चुनने का अधिकार नहीं है।

मिठाई बनाओ या डेज़र्ट स्वाद में लगे सब बेस्ट

अमूल दूध

अमूल दूध पीता है इंडिया



स्वागत



केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने आवास पर परिवार के साथ सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित रहे।

विमल लकड़ा का हाल जानने अस्पताल पहुंचे राज्यपाल



रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने क्यूरेस्टा अस्पताल पहुंचकर पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्यपाल ने वहां उपस्थित चिकित्सकों से श्री लकड़ा के उपचार की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उनके शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य होने की कामना की। उन्होंने कहा कि विमल लकड़ा ने हॉकी के क्षेत्र में देश एवं राज्य को गौरवान्वित किया है। सम्पूर्ण राज्यवासी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना कर रही है।

विमल लकड़ा को फिलहाल ऑपरेशन की जरूरत नहीं : डॉ इरफान अंसारी



नवीन मेल संवाददाता

रांची। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने गुरुवार को अस्पताल जाकर पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री ने डॉक्टरों की टीम को स्पष्ट निर्देश दिया कि उनके इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने उनकी पत्नी और परिजनों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया

कि अब उनकी स्थिति स्थिर है। डॉक्टरों की राय में फिलहाल ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। झारखंड सरकार का पूरा स्वास्थ्य विभाग उनके साथ खड़ा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वह खुद उनके उपचार का निजी रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो देश-विदेश के सर्वश्रेष्ठ न्यूरो सर्जन से उनका इलाज करवाया जाएगा।

देव शयनी एकादशी 6 जुलाई को



नवीन मेल संवाददाता

रांची। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग व श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट के प्रांतीय प्रवक्ता संजय सरॉफ ने कहा है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य दायिनी मानी जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के शयन करने और चातुर्मास के आरंभ का प्रतीक है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन-रविवार को मनाई जाएगी। देव शयनी एकादशी को 'हरि शयनी एकादशी' 'पद्मा एकादशी' और 'आषाढ़ी एकादशी' के नाम से भी जाना जाता

है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। यह निद्रा चार महीनों तक रहती है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु का उत्तरायण से दक्षिणायन गमन होता है, और यह काल तपस्या, व्रत, संयम और भक्ति का होता है। इस एकादशी को समस्त जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी की विधिवत पूजा कर शयन कर दिया जाता है, चातुर्मास में श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, भगवान के शयन के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन जैसे शुभ एवं मांगलिक कार्यों पर अस्थायी रोक लग जाती है।

प्रदेश कांग्रेस का आरोप: उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्र ने संघीय हांचा पर किया प्रहार

झारखंड को उसके जायज हक़ से रखा जा रहा दूर : केशव महतो

नवीन मेल संवाददाता

रांची। रातू रोड फ्लाईओवर सहित अन्य सड़कों के उद्घाटन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने झारखंड की जनता को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का हम स्वागत करते हैं और इसके लिए झारखंड सरकार तत्पर रहती है। लेकिन रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्र द्वारा संघीय ढांचा प्रणाली पर प्रहार किया गया। राज्य के सहयोग को नजरअंदाज करने की पुरानी आदत केंद्र की भाजपा सरकार की रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में आने में असमर्थता जताकर तिथि आगे

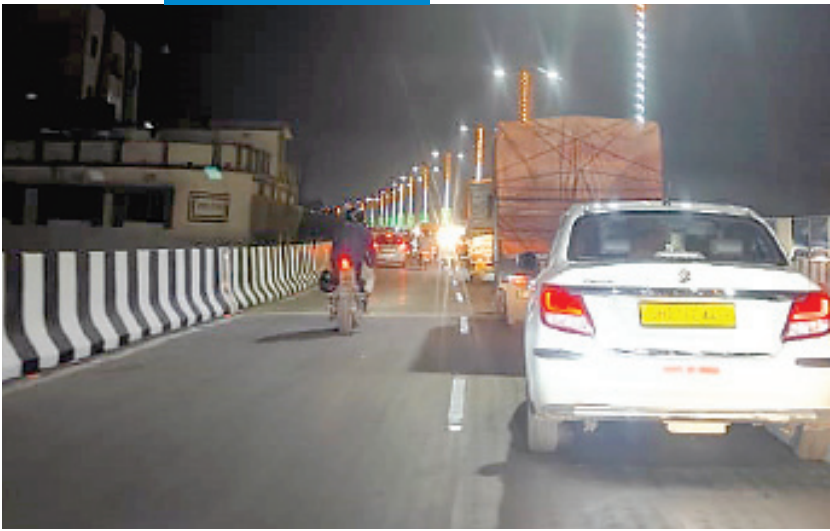
● आज समय है कि राज्य के साथ दोहरे मापदंड से पूरे हटकर झारखंड में विकास की योजनाओं के लिए केंद्र सहयोग करे



देती है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने पूरे देश की योजनाएं झारखंड के लोगों को गिना दी लेकिन जहां पर वह सभा को संबोधित कर रहे थे वहां से प्रारंभ हुये उन्हें रांची बीजूपाड़ा कुड़ फोरलेन की गुगवात के बारे में भी अवश्य कहना चाहिए था, जो

योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है उसके लिए टोल टैक्स की वसूली चालू है, मिंडर के निकट पुल बना नहीं है उसमें गिरकर कई लोगों की मौत हो चुकी है, महज 4 वर्षों के अंदर एन एच 75 की सड़क गदों में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा भले रातू रोड फ्लाईओवर योजना की स्वीकृति की वाह वाहि लट्टेन की कोशिश करे लेकिन सच्चाई है कि विकास के लिए दृढ़ संकल्पित महागठबंधन सरकार ने योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से पूरा सहयोग किया। आज समय है पूरा राज्य को की गुगवात के बारे में ही अवश्य कहना चाहिए था, जो

लगा जाम



उद्घाटन के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर युवाओं से लेकर परिवारों के साथ घूमने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी जो पार्कों की तरह बीच-बीच में खड़ा होकर बोल बतिया रहे थे या सेल्फी ले रहे थे।

झारखंड सरकार का बड़ा कदम

पंचायत सचिवालयों में होगी आधार सेवा केंद्रों की स्थापना

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा कॉमन सर्विस सेंटर - स्पेशल परपज व्हीकल (सीएससी-एसपीवी) के बीच एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह सुविधा अब ग्रामीण जनता को उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें आधार से संबंधित सेवाओं के लिए दूरस्थ



शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम समय, श्रम और संसाधनों की बचत के साथ-साथ डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा देगा। यह पहल झारखंड वित्त नियामक की नियम 245 के अंतर्गत विशेष स्वीकृति के तहत संभव हो पाई है, जिसमें राज्य सरकार ने

सीएससी-एसपीवी को पंचायत भवन में आधार सेवाएं संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस अवसर पर कहा, “यह समझौता झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को डिजिटल

पहचान से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है। इससे न केवल आधार सेवाएं सुलभ होंगी, बल्कि पंचायत सचिवालय डिजिटल सेवा केंद्रों के रूप में सशक्त बनेंगे।”

पुराने सभी इकरारनामों को रद्द कर अब यह नई व्यवस्था यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित इन-हाउस मॉडल के अंतर्गत लागू की जाएगी। इस समझौते के तहत जल्द ही पूरे राज्य में आधार पंजीकरण और उससे जुड़ी सेवाएं पंचायत सचिवालयों से प्रारंभ कर दी जाएंगी।

यह कदम झारखंड सरकार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के संकल्प को गति देने के साथ-साथ डिजिटल भारत के विजन को जमीनी स्तर तक साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नागरमल मोदी सेवा सदन में ‘डॉक्टर्स डे’ मना

नवीन मेल संवाददाता

रांची। नागरमल मोदी सेवा सदन में ‘डॉक्टर्स डे’ समारोह मनाया गया। चिकित्सा अधीक्षक व सभी चिकित्सकों के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए समारोह का शुभारम्भ किया गया। समारोह में सदन के अध्यक्ष अरुण कुमार छावछरिया ने सभी चिकित्सकों का स्वागत करते हुए भारतरत्न डॉ. विद्यानन्द राय की चर्चा की तथा कहा कि चिकित्सक दिवस एक दिन का सम्मान न रहे, हमें हर कदम पर चिकित्सकों को सम्मान, सुरक्षा और



समर्थन देना है। उपाध्यक्ष रेखा जैन एवं सदस्या पाटी कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा “बिगॉड द मास्क केयरिंग फॉर

केयर गीवर्स “ के आधार पर मोनोरंजन कार्यक्रम का संचालन किया। परस्पर सामंजस्य वृद्धि हेतु खेल खिलाया गया एवं विजेताओं

को पुरस्कार भी दिए गए। डॉ. रमन कुमार एवं डॉ. नीशा मोहेश्वरी ने संगीत प्रस्तुत किये। हार्ट सेन्टर के श्री ठाकुर जी ने कविता पाठ किया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर तनिष्क ज्वेलर्स (हरमू रोड) द्वारा सभी चिकित्सकों को अभिनन्दन स्वरूप उपहार दिया गया। कार्यक्रम संयोजक आलोक तुलस्यान ने तनिष्क के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि तनिष्क का अर्थ होता है तन के लिए सोने का गहना किन्तु तन का असली गहना तो स्वास्थ्य ही है इसे चिकित्सक ही पहनाते हैं।

केंद्र सरकार झारखंडवासियों पर टोल टैक्स थोपकर छलावा कर रही है : झामुमो नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की गढ़वा और रांची में सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गुरुवार को हरमू स्थित पाटी कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि हेमंत सरकार ने कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाईं, वह भी बिना किसी टोल के जबकि केंद्र सरकार महंगे ठेके देकर गरीबों से टैक्स वसूलती है। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंडवासियों पर टोल टैक्स थोपकर और ज्यादा



लागत दिखाकर छलावा कर रही है। भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार ने कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर सिर्फ 580 करोड़ रुपये में बनवाए, जबकि केंद्र ने सिर्फ रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पर ही 558 करोड़ खर्च कर दिए। सुप्रियो ने कहा कि गढ़वा बाइपास का उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पहले से ही टोल वसूला जा रहा था। उन्होंने रातू रोड प्रोजेक्ट

रांची की जर्जर सड़कों को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांची। राजधानी रांची की मुख्य सड़कों को छोड़कर अन्य जर्जर सड़कों की मरम्मत को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसएम रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता शुभम कटारूका ने अदालत को बताया कि रांची की कई सड़कें मामूली बारिश में भी तालाब बन जाती हैं। सेवा सदन के सामने की सड़क और तपोवन मंदिर के पास की सड़क की हालत बरसात में अत्यंत दयनीय हो जाती है। रोजाना जान-माल की खतरे का सामना करना पड़ता है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मरम्मत का दावा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की रिपोर्ट परस्पर विरोधाभासी हैं।

न्यूज बॉक्स

मारवाड़ी युवा मंच रांची समर्पण शाखा का सावन मेला 22 से

रांची। मारवाड़ी युवा मंच रांची समर्पण का सावन मेला 22 , 23 , 24 जुलाई को अग्रसेन भवन में लगेगा। शाखा अध्यक्ष ने कहा कि समाज में बहुत सी महिलाएं घर में कुछ सामान तैयार करती हैं , उनको सेल करने के लिए शाखा उन्हें एक प्लेटफार्म देती है, ताकि महिलाएं अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें। मेले में राखी, कुर्ती, बेडशीट, होम मेड आइटम वगैरह के स्टॉल रहेंगे। मेले में शॉपिंग के अलावा फूड स्टॉल एवं गेम्स भी रहेंगे। स्टॉल की बुकिंग लगभग पूरी हो गई है। शाखा ने सभी रांचीवासियों से मेले में विजिट करने का आग्रह किया है। मीडिया प्रभारी सरिता बथवाल ने कहा मेले से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए संयोजिका से संपर्क करें।

माइकल राज एस झारखंड पुलिस के प्रवक्ता नियुक्त

रांची। आईजी अभियान माइकल राज एस को झारखंड पुलिस का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले माइकल राज एस बोकारो जोनल आईजी के पद पर पदस्थापित थे। बीते दिन हुए आईपीएस के ट्रांसफर-पोस्टिंग के दौरान सरकार ने इन्हें आईजी अभियान के पद पर पदस्थापित किया है।



भाजपा की नीतियों के विरोध में झामुमो ने किया पुतला दहन



रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रांची जिला समिति ने भोगनाडीह में हूल दिवस के अवसर पर हुई घटना और भाजपा की आदिवासी-विरोधी नीतियों के खिलाफ फिरायालाल चौक स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम ने किया। इस अवसर पर मुस्ताक आलम ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा झारखंड को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। भोगनाडीह में साड़ी, पैसा और हथियार बांटकर जनता को उकसाया गया ताकि संथाल परगना को मणिपुर जैसा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह विरोध झारखंड के 24 जिलों में हो रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित है। मौके पर कई अन्य झामुमो नेताओं ने कहा कि वे झारखंड में शांति और सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। किसी भी तरह की सांप्रदायिक या विघटनकारी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। पुतला दहन कार्यक्रम में पवन जेठिया, अश्विनी शर्मा, डॉ हेमलाल मेहता, बीरू तिकी, धर्मेन्द्र सिंह, अंतु तिकी, जनक नायक, कलाम आजाद, आदिल इमाम, संजय राय, रमेश साहू, फरीद खान, आफताब आलम, जीत गुप्ता, महावीर विश्वकर्मा, अरुण वर्मा, लालजी रमण, मृत्युंजय सिंह, आशुतोष वर्मा, मो निजाम, सुनील साहू, सुजीत कुंजूर, शिवनंदन मिश्रा, सुजीत उपाध्याय, परवेज आलम गुड्डा, बबलू राम, अजीत नायक सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

पृष्ठ एक के शेष

गडकरी के एलिवेटेड कॉरिडोर से...

कि रास्ते अच्छे हुए तब अमेरिका धनवान हुआ। गडकरी ने कहा कि 2 साल के अंदर देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बाबर हो जाएगा। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहें हैं। दिल्ली से जयपुर दो घंटा, मैसूर से बेंगलुरु एक घंटा मेट्रो से दिल्ली 45 मिनट, दिल्ली से अमृतसर 4:30 घंटा, घंटा दिल्ली से कटरा 6 घंटा मुंबई से दिल्ली के सफर में अब 12 घंटा का समय लगेगा।

जमीन विवाद और फॉरेस्ट क्लियरेंस में मांगा राज्य सरकार का सहयोग : उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फोन करके दिल्ली से आने में असमर्थता जताई। उनसे अनुरोध करूंगा कि जमीन अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस देंगे, तो कई काम हो जाएंगे। इससे पहले नितिन गडकरी ने बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में महुआ माजी और राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा भी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री अन्नुर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, कई सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारी भी इस समारोह में मौजूद रहे।

नितिन गडकरी ने इन योजनाओं का किया लोकार्पण : नागा बाबा खटाल से नितिन गडकरी ने झारखंड को 6300 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। उन्होंने 1900 करोड़ की लागत से पलमा से गुमला तक बने फोर लेन सड़क, 560 करोड़ रुपए की लागत से रांची शहर में रातू रोड पर बने एलिवेटेड कॉरिडोर, 70 करोड़ की लागत से बने बाघाहाट से तुलसीपुर खंड तक 2 लेन पेव्ड शोल्लडर के चौड़ीकरण, 825 करोड़ की लागत से बने बरही-कोडरमा खंड फोर लेन, 100 करोड़ की लागत वाली गोड्डा से सुंदरपहाड़ी खंड तक 2 लेन पेव्ड शोल्लडर के चौड़ीकरण, 20 करोड़ की लागत से गिरिडीह शहर में सड़क के चौड़ीकरण और 1130 करोड़ की लागत से शंखा से खजुरी तक बने फोर लेन सड़क का लोकार्पण किया।

40 साल से रातू रोड का सपना था फ्लाईओवर : संजय सेठ

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नितिन गडकरी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि शेरशाह सूरी के नाम को सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया गया है। रांची के लिए 40 साल से रातू रोड का सपना था फ्लाईओवर। लाल मिट्टी से लेकर कालीकरण के लिए ऑबोलन करना पड़ता था लोगों को जाम से जूझना पड़ता था। आज वो सपना पूरा हो गया। उन्होंने नितिन गडकरी से आउटर रिंग रोड, एलिवेटेड कॉरिडोर पर के पिछर पर सोहरामथी पेंटिंग, रांची अमगड़ा सिल्ली मुरी सड़क को फोरलेन करने के साथ रांची में इलेक्ट्रिक बस के संचालन की मांग की।

राजनेताओं ने जताई खुशी : पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इन परियोजनाओं को झारखंड के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा, “2014-19 के दौरान डबल इंजन सरकार ने सड़क यातायात को सुगम बनाने की योजनाएं बनाईं थीं, जो आज पूरी हुई हैं। सहविग्न सड़क निर्माण ने संताल की दूरी को कम किया है।” बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, “नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। नितिन गडकरी सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। हेमंत सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा ने केंद्र को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नुर्णा देवी ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि घंटों की दूरी मिटने में तय होगी।

हमारी दोस्ती घाना के प्रसिद्ध...

आपका राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सम्मान है और मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगा। उन्होंने कहा कि भारत को अक्सर लोकतंत्र की जनीनी कहा जाता है। हमारे लिए लोकतंत्र केवल एक की व्यवस्था नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, जो हमारे मौलिक मूल्यों में गहराई से निहित है। हजारों वर्षों से हमने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखा है। वैशाली के प्राचीन गणराज्य से लेकर दुनिया के सबसे पुराने शासकों में से एक ऋग्वेद के ज्ञान तक, जिसमें कहा गया है, 'सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आएंगे।' विचारों के प्रति यह खुलापन हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार के मूल में है। आज भारत में 2,000 से अधिक राजनीतिक दल, 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। यह विविधता कोई चुनौती नहीं है। यह हमारी ताकत है। यही कारण है कि सदियों से भारत आने वाले लोगों का हमेशा खुले दिल से स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको अनुमति से मैं कह सकता हूँ कि हमारी दोस्ती घाना के प्रसिद्ध राश्ट्र राश्ट्र लोफ अनावास से भी ज्यादा मीठी है। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ मिलकर हम अपने संबंधों को एक व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षणों में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। जब भारत ने चंद्रमा के सउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी मैं अफ्रीका में था और आज जब एक भारतीय अंतरिक्ष यानो मानवाता के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भी मैं अफ्रीका में हूँ। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

269
रन

तिहरे शतक से
चूके शुभमन गिल

पहली पारी में भारत 587 रन पर आउट

एजबेस्टन। कप्तान शुभमन गिल के 269, रवींद्र जडेजा के 89 और यशस्वी जायसवाल के 87 रनों की मदद से भारतीय टीम ने एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में अपनी पहली पारी में 587 रन बनाए। दूसरे दिन चायकाल के बाद जब खेल शुरू हुआ तो सबकी नजर भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर थी। वह 265 पर नाबाद थे। उम्मीद की जा रही थी कि वह तिहरा शतक पूरा करेंगे। लेकिन, तीसरा सेशन शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही वह 269 रन के स्कोर पर आउट हो गए। 387 गेंद की पारी में गिल ने तीन छक्के और 30 चौके लगाए। टेस्ट में गिल का यह पहला दोहरा शतक है। साथ ही किसी भी भारतीय कप्तान का बनाया यह सर्वाधिक स्कोर भी है। इस पारी के दौरान शुभमन गिल ने इंग्लैंड में भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1990 में मैनचेस्टर में 179 रन बनाए थे। वहीं, 2018 में विराट कोहली के बनाए 149 के आंकड़े को पार करते ही एजबेस्टन के मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बन गए। भारतीय टीम को 587 रन तक पहुंचाने में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रवींद्र जडेजा का अहम रोल रहा। जायसवाल ने 107 गेंद पर 87 रन की पारी खेली। इस दौरान करुण नायर के साथ उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 80 और गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 66 रन की अहम साझेदारियां निभाईं। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रवींद्र जडेजा ने 89 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने कप्तान गिल के साथ छठे विकेट के लिए 203 रन की अहम साझेदारी की। वाशिंगटन सुदूर ने 42 रन बनाए और गिल के साथ सातवें विकेट के लिए 114 रन जोड़े। करुण नायर ने 31, ऋषभ पंत ने 25 रन बनाए। इंग्लैंड ने सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। शोएब बशीर ने तीन विकेट लिए। क्रिस वोक्स-जोश टंग को दो-दो विकेट मिले। स्टोक्स, कार्स, जो रूट ने एक-एक विकेट चटकका। टॉस इंग्लैंड ने जीता था।

‘पुरानी दिल्ली 6’ से जुड़े रहेंगे ऋषभ पंत



नई दिल्ली। ‘पुरानी दिल्ली 6’ ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के आगामी सत्र के लिए स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में बनाए रखने का ऐलान किया है। पंत को मार्की खिलाड़ी के तौर पर टीम में बनाए रखा गया है। पुरानी दिल्ली 6 ने डीपीएल 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। ऐसे में टीम दुर्भाग्यवश खिताब से दूर रह गई। ऋषभ पंत के टीम में बने रहने से उम्मीद है कि 2025 सत्र में पुरानी दिल्ली 6 और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगी। ऋषभ पंत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “डीपीएल युवा प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। इस लीग के सफल आयोजन का श्रेय रोहन जेटली और डीडीसीए को जाता है। डीपीएल के जरिए प्रदान किए गए मौकों से देशभर के कई खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं, जैसे कि दिग्वेश राठी और प्रियांश आर्य।” पंत ने कहा, “मेरे लिए पुरानी दिल्ली 6 सच में घर जैसा है। पिछले साल एक शानदार सीजन के बाद, सफल होने का हमारा दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हुआ है। हम इस साल और भी मजबूत होकर लौटना चाहते हैं।” पुरानी दिल्ली 6 के मालिक आकाश नांगिया ने कहा, “ऋषभ पंत न केवल एक विश्व स्तरीय क्रिकेटर हैं, बल्कि पुरानी दिल्ली 6 की धड़कन भी हैं। उनका नेतृत्व, अनुभव और स्वभाव से हमें बहुत मिलती है। हम उनके इर्द-गिर्द एक मजबूत टीम बना रहे हैं। हमें इस साल आगे बढ़ने का पूरा भरोसा है।”

नीरज चोपड़ा से मिले
कर्नाटक के सीएम
सिद्धारमैया

कर्नाटक। ओलंपिक पदक विजेता और वर्ल्ड नंबर-1 जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उनके कावेरी स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नीरज चोपड़ा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य गोविंदराजू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर नीरज चोपड़ा से मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में सिद्धारमैया नीरज चोपड़ा को माला, शॉल और पगड़ी पहनाते दिखे। मुख्यमंत्री ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, “दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और दुनिया के सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रो खिलाड़ियों में से एक नीरज चोपड़ा ने मुझसे मुलाकात की। इस मौके पर मैंने उनको खेल करियर में निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।” इस मौके पर ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य गोविंदराजू भी मौजूद थे। पांच जुलाई को कांतिवा स्टेडियम में होने वाली ‘नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन’ में हिस्सा लेने के लिए नीरज चोपड़ा बेंगलुरु में हैं। ‘नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन’ भारत में होने वाला पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स ‘ए’ कैटेगरी या कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड लेवल का इवेंट होगा।



सात साल में थामा बैडमिंटन रैकेट जोड़ीदार के साथ मिलकर रचा इतिहास

नई दिल्ली। चार जुलाई 1997 को मुंबई के मलाड में जन्मे चिराग शेट्टी भारत के स्टार शटलर हैं। विश्व स्तर पर कई बड़े टूर्नामेंट्स जीत चुके चिराग ने महज सात साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। चिराग गोरगांव स्पोर्ट्स क्लब में उदय पवार बैडमिंटन अकादमी में बैडमिंटन के गुरु सीखने पहुंचे। इसके बाद चिराग ने हैदराबाद स्थित पुल्लु गोपीचंद अकादमी में ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जहां उनकी मुलाकात सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी से हुई। चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी ने यहां बैडमिंटन के गुरु सीखे। इसी जोड़ी ने आगे भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। जोड़ी ने कड़ी मेहनत और शानदार तालमेल के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई। कोर्ट पर अपनी ताकत और स्किल के दम पर कई टूर्नामेंट जीते। इस जोड़ी को ‘सात्विक’ के नाम से बुलाया जाता है। चिराग शेट्टी ने साल 2016 में एशियन टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद साल 2018 में कॉमनवेल्थ के दौरान मिक्सड टीम इवेंट में गोल्ड और मॅस डबल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद चिराग शेट्टी ने एशियन टीम चैंपियनशिप-2020 में एक बार फिर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। साल 2022 चिराग शेट्टी के लिए बेहद खास रहा। इस साल उन्होंने देश को थॉमस कप में गोल्ड, जबकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज दिलाया। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीते। इसके अलावा एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीते। साल 2023 में चिराग शेट्टी एशिया मिक्सड टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। चिराग ने साल 2023 में सात्विक के साथ तीन बीडब्ल्यूएफ खिताब जीते। इनमें इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन और रिवस ओपन थे। अक्टूबर 2023 में यह जोड़ी बैडमिंटन रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 जोड़ी बन गई। यह कारनामा किसी भारतीय जोड़ी ने पहली बार किया था। चिराग शेट्टी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया।

फुटबॉलर डिओगो जोटा की कार दुर्घटना में मौत



जमोरा (स्पेन)। लिवरपूल और पुर्तगाल के फॉरवर्ड डिओगो जोटा की स्पेन में गुरुवार को 28 साल की उम्र में कार दुर्घटना में मौत हो गई। स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के समय जोटा अपने भाई के साथ कार में थे। प्रीमियर लीग और लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर फुटबॉलर के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।



सत्यमेव जयते
भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय



'नारी शक्ति के लिए नए अवसर'

सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान,
के क्षेत्रीय केंद्र, रांची के उद्घाटन के अवसर पर

समस्त झारखंडवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ

"हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, विकसित भारत के संकल्प में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं
बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं।"

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

रांची केंद्र के खुलने से लाभ:

देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों - झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को मिलेगा लाभ और मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं की विशिष्ट प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को किया जाएगा पूरा।

केंद्र द्वारा बाल मार्गदर्शन एवं परामर्श में एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

उद्घाटन समारोह

मुख्य अतिथि

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

माननीय केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

गरिमानयी उपस्थिति

श्री संजय सेठ

माननीय राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय

श्री नवीन जयसवाल

माननीय विधायक, हटिया

श्रीमती सावित्री ठाकुर

माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

श्री राजेश कच्छप

माननीय विधायक, खिजरी

दिनांक : 4 जुलाई 2025, शुक्रवार

स्थान : सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, झारखंड शहरी नियोजन एवं प्रबंधन संस्थान, एचईसी मुख्यालय के पास, धुर्वा, रांची, झारखंड

CBC 4610/13/0013/2526